

देश में कोरोना सक्रिय मामले घटकर सात हजार से नीचे आये

नई दिल्ली। देश में पिछले तीन दिनों के दौरान कोरोना सक्रिय मामलों में कमी देखी गयी है और मंगलवार सुबह तक सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 6836 रही गयी। इससे पहले रविवार और सोमवार को कुल सक्रिय मामलों की संख्या क्रमशः 7383 और 7264 थी। पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण से एक और मरीजों की मौत होने से मृतकों का आंकड़ा 109

पहुंच गया है और 428 मामले घटने के साथ इनकी कुल सक्रिय मामलों की संख्या 6836 रह गयी। वहीं 1168 मरीजों के स्वस्थ होने से अभी तक इस वायरस से निजात पाने वालों की कुल संख्या 14772 पहुंच गयी है। गत 22 मई को देश में कोरोना के मामले सिर्फ 257 सक्रिय थे। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से आज जारी आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमण से एक मरीज की मौत हुयी है। इस अवधि में जहां 14 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेश में कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी, वहीं 11 राज्यों में सक्रिय मामलों में कमी आयी है।

पिछले 24 घंटों में जहां कोरोना संक्रमण के सबसे अधिक सक्रिय मामले कर्नाटक से 105, हरियाणा से 12, पंजाब से 10 और राजस्थान से 29 मामले सामने आये हैं और वहीं केरल में 261, दिल्ली में 94, गुजरात में 185 और महाराष्ट्र में 28



मामले कम हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार संक्रमण के नये उभरते वैरिएंट, विशेष रूप से एलएफ.7, एक्सएफजी, जेएन.1

और हाल ही में पहचाने गये एनबी.1.8.1 सबवैरिएंट के कारण हो रहा है। इन वैरिएंट्स की जांच चल रही है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार देश के 32 राज्यों और केन्द्रशासित प्रदेशों में से 29 में कोरोना के सक्रिय मामले सामने आये हैं, जबकि तीन राज्यों मिजोरम, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमण का अभी कोई सक्रिय मामला नहीं है। मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार

संक्रमण के मामलों में केरल सबसे अधिक प्रभावित राज्य है, हालांकि आज सुबह तक 261 सक्रिय मामले कम होने के साथ इसका आंकड़ा 1659 रह गया है। राष्ट्रीय राजधानी में 94 मामले घटने से संक्रमितों की कुल संख्या घटकर 555 रह गयी। महाराष्ट्र में 28 मामले घटने से संक्रमितों की कुल संख्या घटकर 512 रह गयी और गुजरात में इसके मामलों की संख्या घटकर 1248 रह गयी है। इसके अलावा पश्चिम

मणिपुर में भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद बरामद, एक उग्रवादी गिरफ्तार

एजेंसी इफाला। मणिपुर पुलिस ने बोते 24 घंटों के दौरान विभिन्न इलाकों में चलाए गए तलाशी अभियानों के दौरान भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और संचार उपकरण बरामद किए हैं। साथ ही एक उग्रवादी को भी गिरफ्तार किया गया है। पुलिस प्रवक्ता ने मंगलवार को बताया कि थौबल जिले के नोंगपोक सेक्टर में नहर के पास से पुलिस ने तलाशी के दौरान एक .303 राइफल और मैगजीन, एक डीबीबीएल गन, एक 9मिमी पिस्टल और मैगजीन, दो 9मिमी जिंदा कारतूस, दो 12 बोर कारतूस, चार एचई हैंड ग्रेनेड (नं. 36), चार डेटोनेटर, चार अर्मांग रिंग, दो एमके-III एंड ग्रेनेड, दो स्टन शेल (एन), तीन टीयर स्मोक शेल (सॉफ्ट नोज), एक टीयर स्मोक शेल (चिल्ली) तथा दो बाओफेंग रेडियो सेट चार्जर बरामद किए। इसी तरह इफाला वेस्ट जिले के पत्सोई थाना क्षेत्र के संगईथेल माखा लेइकाई से एक 7.62 मिमी एमएलआर राइफल और दो मैगजीन बरामद किए गए। संगईथेल और हेइबिलोक क्षेत्रों से पुलिस ने एक एक्सकैलिबर राइफल (2 जिंदा 5.56 मिमी राउंड सहित), तीन बोल्ट-एक्शन राइफल (बिना मैगजीन), एक देशी 9मिमी पिस्टल और मैगजीन, चार 12 बोर जिंदा कारतूस तथा दो बाओफेंग वॉकी-टॉकी बरामद किए। इसके अतिरिक्त, चुराचांदपुर जिले के तुइबोंग क्षेत्र से सीकेएनडीएफ/ए (गैर-एसओओ समूह) के एक कैडर नागामखोसात तैथांग उर्फ सासात (38) को उसके निवास से गिरफ्तार किया गया।

उसके खिलाफ म्यांमार से हथियार व ड्रग्स तस्करी, फिरीती वसूली और अपहरण जैसे मामलों में केस दर्ज हैं। उल्लेखनीय है कि 16 मई को इसकी छिपने की जगह से भी एक देशी पिस्टल, तीन 9 मिमी कारतूस और सीकेएनडीएफ/ए के पांच लेटरहेड बन्द किए गए थे। पुलिस ने बताया कि तलाशी अभियान और गिरफ्तारियों का उद्देश्य राज्य में असमाजिक तत्वों पर लगाम कसना और शांति बहाल करना है।

अमरनाथ यात्रा मार्ग एक जुलाई से नो फ्लाईंग जोन घोषित

एजेंसी श्रीनगर। आगामी अमरनाथ यात्रा के लिए पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार ने पूरे तीर्थयात्रा मार्ग को नो फ्लाईंग जोन घोषित कर दिया है। केंद्र शासित प्रदेश के गृह विभाग ने अमरनाथ यात्रा के सभी मार्गों को नो फ्लाईंग जोन घोषित कर दिया है जिसमें पहलगाम और बालटाल दोनों मार्ग शामिल हैं। यह प्रतिबंध सभी प्रकार के हवाई उपकरणों पर लागू होता है जिसमें यूएवी, ड्रोन और गुब्बारे शामिल हैं।

सुरक्षा निर्देश 01 जुलाई से 10 अगस्त तक लागू रहेंगे। यह निर्णय केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा ऐसा करने की सलाह दिए जाने के बाद लिया गया है। यह प्रतिबंध चिकित्सा निकासी, आपदा प्रबंधन या सुरक्षाबलों द्वारा किए जाने वाले निगरानी अभियानों के मामलों पर लागू नहीं होंगे। ऐसे अपवादों के लिए विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) बाद में जारी की जाएगी। वार्षिक अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त को समाप्त होगी। पहलगाम हमले के मद्देनजर यात्रा के सुचारु और शांतिपूर्ण संचालन के लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए जा रहे हैं। तीर्थयात्रा के लिए केंद्रीय सशस्त्र अर्धसैनिक बलों (सीएपीएफ) की 580 कंपनियों को तैनात किया जा रहा है।



मोहल्ला क्लीनिक था भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा : रेखा गुप्ता

नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिछली सरकार की मोहल्ला क्लिनिक को भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा करार देते हुए कहा है कि इलाज के नाम पर जनता को सिर्फ धोखा दिया गया। श्रीमती रेखा गुप्ता ने मंगलवार को तीस हजारी कोर्ट परिसर में आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन करने के बाद कहा कि पिछली सरकार में मोहल्ला क्लिनिक की क्या स्थिति थी यह किसी से छिपी नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा, मोहल्ला क्लिनिक पूरी तरह से घोटाला था। इसमें न देखभाल थी, न दवाएँ। इसका एकमात्र उद्देश्य पैसा कमाना था। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर नालों और गंदी जगहों पर पोटा केबिन में इसे खोला गया जहाँ प्रति मरीज 40 रुपये के हिसाब से डॉक्टर को भुगतान किया जाता था। ऐसी स्थिति में इलाज की गुणवत्ता की कल्पना की जा सकती है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही मोहल्ला क्लिनिक बनाने के नाम पर जो किराए पर जगह ली गई उसमें भी कई गुना अधिक भुगतान किया गया। मोहल्ला क्लिनिक पिछली सरकार के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा अड्डा था। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में आज एक साथ 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और 17 जन औषधि केंद्रों का उद्घाटन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से पाँच साल पहले 2400 करोड़ रुपये धनराशि दिल्ली सरकार को दी गई, लेकिन पिछली सरकार ने अपने अहम के चक्कर में इस धनराशि का इस्तेमाल नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार बनने के बाद उस धनराशि का इस्तेमाल किया जा रहा है और अगले साल मार्च तक 1140 आरोग्य मंदिर बनाने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आरोग्य मंदिर और मोहल्ला क्लिनिक में जमीन आसमान का फर्क है। उन्होंने कहा कि जहाँ-जहाँ आरोग्य मंदिर खुलते जाएँगे वहाँ पर मोहल्ला क्लिनिक को बंद कर दिया जाएगा। आरोग्य मंदिर में हर प्रकार की जाँच की सुविधा होगी और वहाँ क्वालिफाइड डॉक्टर होंगे। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने जनऔषधि केंद्र सिर्फ इसलिए नहीं खोले क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री जुड़ा था, लेकिन हमारी सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों में जनऔषधि केंद्र खोलने का निर्णय लिया है और आज 17 जनऔषधि केंद्र खोले गए हैं। वहीं दिल्ली के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) मंत्री प्रवेश साहनि सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र के बाबर रोड पर आयुष्मान आरोग्य मंदिर का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा आज दिल्ली में स्वास्थ्य क्रांति का दिवस है। दिल्ली के लिए 33 आयुष्मान आरोग्य मंदिर और सस्ती दवाओं के लिए 17 नए जनऔषधि केंद्र, सिर्फ 100 दिन में केंद्र सरकार की संकल्पशक्ति और दिल्ली की नई सरकार की कार्यशक्ति का परिणाम है। इसके अलावा दिल्ली के सभी कैबिनेट मंत्री अपने-अपने निर्वाचन क्षेत्रों में इन केंद्रों का उद्घाटन करेंगे।



अहमदाबाद विमान दुर्घटना:कैप्टन समरवाल का पार्थिव शरीर मुंबई पहुंचा

मुंबई। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में मारे गये एयर इंडिया के विमान 171 के कैप्टन सुमीत सभरवाल का पार्थिव शरीर मंगलवार सुबह मुंबई के पवई स्थित उनके आवास पर लाया गया। यह विमान 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया था जिसमें चालक दल के सदस्यों समेत 241 लोग मारे गए थे। बड़ी संख्या में लोग कैप्टन सभरवाल के निवास के पास अंतिम प्रदंडांजलि और शोक संतप्त परिवार को संवेदना देने के लिए इकट्ठा हुए। पवई स्थित जल वायु विहार में शोक की लहर छा गई। यह एक आवासीय परिसर है जिसमें सेवानिवृत्त वायुसेना अधिकारी और विमानन कर्मी रहते हैं।



सीएम भजनलाल शर्मा ने लिखा केंद्रीय जल शक्ति मंत्री को पत्र तीन बड़ी जल परियोजनाओं को जल्द लागू करने का किया आग्रह

एजेंसी जयपुर। राजस्थान को बड़ी राहत मिल सकती है। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल को एक अहम पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने चिनाब नदी बेसिन से जुड़ी तीन बड़ी जल परियोजनाओं को जल्द लागू करने का आग्रह किया है। इन प्रस्तावों से चिनाब जैसी हिमालय से निकलने वाली नदियों का अतिरिक्त पानी अब ब्यास, रावी और उझ जैसी पूर्व की ओर बहने वाली नदियों में लाया जा सकेगा। इससे उत्तर भारत के कई राज्यों के साथ-साथ राजस्थान को भी बड़ा फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने लिखा- राजस्थान को करीब 1.0 MAF (मिलियन एकड़ फीट) पीने के पानी के लिए, 1.0 MAF सिंचाई के लिए और 0.2 इंच औद्योगिक जरूरतों के लिए पानी की जरूरत है। साथ ही, राजस्थान के पास पहले से मौजूद



1. ब्यास और सतलुज नदी में अतिरिक्त पानी पहुंचाए, जिससे हरियाणा, पंजाब, दिल्ली के साथ-साथ राजस्थान को भी फायदा मिलेगा।

2. इंदिरा गांधी नहर को और ज्यादा पानी मिल सकेगा, जिससे पश्चिमी राजस्थान की बड़ी आबादी को सिंचाई और पीने के लिए राहत मिलेगी।

3. औद्योगिक क्षेत्रों को जल आपूर्ति आसान होगी, जिससे नए निवेश और रोजगार के रास्ते खुलेंगे।

जातीय जनगणना का कार्य देशहित में समय और ईमानदारी से पूरा होना चाहिए : मायावती

एजेंसी लखनऊ। केंद्र सरकार ने जातीय जनगणना करने की तिथियों का ऐलान कर दिया है। इसको लेकर राजनेता अपनी-अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। इसी बीच बहुजन समाज पार्टी (बसपा) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने कहा कि जनकल्याण से सीधे तौर पर जुड़ा जातीय जनगणना का कार्य देशहित में अब समय से ईमानदारीपूर्वक पूरा होना चाहिए। केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे। बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को एक्स पर एक पोस्ट कर कहा, भाजपा ने केंद्र में अपने 11 वर्षों के कार्यकाल के बारे में जो अपार उपलब्धियाँ गिनाईं, जो जमीनी हकीकत में लोगों की गरीबी, बेरोजगारी, दुख-दर्द आदि दूर



समय आने पर जनता खुद उनको इसका जवाब देगी। उन्होंने कहा कि

देश में राष्ट्रीय व जातीय जनगणना का भी कार्य कांग्रेस के समय से

मामले में प्रक्रिया शुरू हुई है। जनगणना का कार्य समय व ईमानदारी से पूरा होना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि इन मामलों में पार्टी के लोगों को सही तथ्यों से अवगत कराने व उन्हें सजग करने के साथ ही पार्टी के संगठन के सम्बन्धित दिये गए कार्यों की समीक्षा की जा रही है। उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की भी छेटी-छेटी बैठकों के जरिए विचार-विमर्श लगातार जारी है। साथ ही साथ ही पार्टी हित में इन पर पूरा ध्यान जरूरी है। उन्होंने कहा कि बिहार में होने वाले विधानसभा आमचुनाव से सम्बन्धित रणनीति पर भी तैयारी जारी है, ताकि बेहतर परिणाम मिल सकें।

योग बंधन में किया योगाचार्यों ने योग

एजेंसी नयी दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान ने अंतरराष्ट्रीय योग दिवस की तैयारी के मद्देनजर मंगलवार को योगाभ्यास का आयोजन किया जिसमें दुनिया भर से योग संस्थाओं के प्रमुखों ने हिस्सा लिया।

संस्थान के प्रांगण में आयोजित योग सत्र में योग ऑस्ट्रेलिया के अध्यक्ष जोश प्रायर, ऑस्ट्रेलिया में योग इन डेली लाइफ के बरिष्ठ प्रतिनिधि ग्रेगर कोस, ब्राजील में साओ पाउलो विश्वविद्यालय के योगाभ्यास का आयोजन किया जिसमें दुनिया भर से योग की संस्थाएँ यिन यान, डेनमार्क के योग विशेषज्ञ मेजर इगेमैन-मोल्डेन, इंडोनेशिया के इंडोनेशियाई राष्ट्रीय योग चिकित्सक संघ के अध्यक्ष सलामत रियातो, कजाकिस्तान में शक्ति योग स्टूडियो की निदेशक विद्या वोल्कोवा, मलेशिया के मलेशिया योग सोसायटी और मलेशिया योग प्रशिक्षक संघ के संस्थापक मणिसेकन और मलेशिया में अक्सिनोम योग

की सह संस्थापक सिंथामनी अरुणासलम शामिल हुए। इनके अलावा रूस में योग चिकित्सक इरीना फुरसोवा, योग चिकित्सक, सिंगपुर में पेन्ना योग और वेल्स की निदेशक डॉ. सुजाता कासली, दक्षिण कोरिया में प्रतिष्ठित इंडोलांजिस्ट पुरस्कार 2019 के प्राप्तकर्ता प्रो. जियो-लियोंग ली, दक्षिण अफ्रीका में योग शिक्षक

कुगन नायडू, दक्षिण अफ्रीका में योग विशेषज्ञ सिवतुचिनायडू, स्पेन में प्रसिद्ध योग चिकित्सक जोस मारिया मार्केज़ जुगोडे (गोबाल), श्रीलंका के फिल्म निर्माता विमलविक्रम जयसूरदा और अर्जेंटीना में सांता फे प्रांत के प्रतिनिधि रोसियो बेलेन बोनाची ने भी योगाभ्यास किया।

गई थी। इंडिगो की फ्लाइट 6ई 2706 ने कोच्चि से दिल्ली के लिए उड़ान भरी थी। विमान को बम की धमकी के बाद नागपुर में



आपातकालीन लैंडिंग करानी पड़ी। पुलिस और अग्निशमन दल विमान को जांच कर रहे हैं। सुबह ही सैन फ्रांसिस्को से मुंबई आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट को कोलकाता में खाली कराया गया था। सैन फ्रांसिस्को से कोलकाता होते हुए मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के इंजन में तकनीकी खराबी आई, जिसके कारण मंगलवार को शहर के एयरपोर्ट पर

गया था। इस फ्लाइट ने अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन कुछ देर बाद ही विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस विमान में 230 यात्री और चालक दल के 12 सदस्य सवार थे। इस हादसे में केवल एक यात्री विश्वास कुमार रमेश जीवित बचे, जो सीट नंबर 11ए पर बैठे थे। वह भारतीय मूल के ब्रिटिश नागरिक हैं।

‘ढग लाइफ’ पर प्रतिबंध से सुप्रीम कोर्ट नाराज, कर्नाटक सरकार से मांगा 24 घंटे में जवाब

एजेंसी नई दिल्ली। मशहूर फिल्म अभिनेता कमल हासन की मुख्य भूमिका वाली फिल्म ‘ढग लाइफ’ को आवश्यक कानूनी प्रावधानों को पालन किये बिना कर्नाटक के सिनेमाघरों में प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाने पर कड़ी आपत्ति जताते हुए राज्य सरकार को अगले 24 घंटे के अंदर जवाब देने का मंगलवार को निर्देश दिया। न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां और न्यायमूर्ति मनमोहन की अंशकालीन कार्य दिवस पीठ ने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली महेश रेड्डी की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह दलील दिए जाने के बाद कि इस विवाद के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, पीठ ने



द्वारा प्रमाणित हो जाती है तो भीड़ थिएटर मालिकों को डरा धमकाकर उसके प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध लगाने पर मजबूर नहीं कर सकती। दिवस पीठ ने प्रतिबंध को चुनौती देने वाली महेश रेड्डी की ओर से दायर एक जनहित याचिका पर यह आदेश पारित किया। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से यह दलील दिए जाने के बाद कि इस विवाद के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय में एक याचिका दायर की गई है, पीठ ने

हज 2026 के इच्छुक लोगों को पासपोर्ट तैयार रखने की सलाह

एजेंसी
नई दिल्ली।हज 2026 की घोषणा जुलाई 2025 में संभावित है, क्योंकि सऊदी अरब के हज और उमरा मंत्रालय ने हज 2026 (हिजरी 1447) के लिए प्रशासनिक दिशा-निर्देश 8 जून को जारी कर दिए हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शानवास सी. ने एक परिपत्र में भारत के उन तमाम इच्छुक लोगों को सुझाव दिया है, जो हज 2026 (1447 हिजरी) में हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से यात्रा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि वह अपना मशीन रीडेबल अंतरराष्ट्रीय पासपोर्ट, पहले से तैयार रखें, जिसकी वैधता कम से कम 31 दिसंबर 2026 तक हो।

भाजपा विधायको ने बांग्लादेश में रबिंद्र नाथ टैगोर के पैतृक निवास संग्रहालय पर सुनियोजित तोड़फोड़ के खिलाफ किया प्रदर्शन

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में सोमवार को भाजपा सांसदों और विधायकों ने नई दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग पर बांग्लादेश में भारत रत्न गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के पैतृक आवास को तोड़े जाने पर विशाल प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि रविन्द्र नाथ टैगोर वह महान पुरुष हैं जिनकी लिखी गए दो गीत दो देशों भारत और बांग्लादेश के राष्ट्र गान हैं। उन्होंने कहा कि उनके पैतृक घर पर सुनियोजित तरीके से तोड़फोड़ करना सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि यह बांग्ला संस्कृति पर हमला है। यह हिंदू संस्कृति पर हमला है। सचदेवा ने कहा कि बांग्ला संस्कृति गाना, गीतों वालों, कला और कल्चर की बातें करती है लेकिन उसे अगर कोई अपमानित करने की कोशिश करेगा तो हिंदुस्तान का हर व्यक्ति आवाज उठाएगा। उन्होंने कहा कि भारत अगर किसी देश की सहायता करता है तो उस देश में हिंदुओं के साथ हो रहे अन्याय पर चुप नहीं बैठने वाला है। दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ने साविलया लहजें में पूछ कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान आमार बांग्ला सोनार जिसका मतलब है कि मेरा सोने का बंगाल लेकिन आज उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या आज बांग्लादेश सोना रह गया है क्या?

दिल्ली महापौर ने एमसीडी के 200 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी किए पत्र प्रदान

नई दिल्ली। दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने दुर्घटना में पैर गंवाने वाले सफाई कर्मचारी शीशा पाल के आश्रित पुत्र को दिल्ली नगर निगम में नियमित आधार पर चौकी का नियुक्ति का पत्र प्रदान किया। इसके साथ ही एमसीडी के 200 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी पत्र भी प्रदान किए। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए दिल्ली के महापौर राजा इकबाल सिंह ने कहा कि नगर निगम की भाजपा सरकार निगम के सफाई कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील है। इकबाल सिंह ने कहा कि दिल्ली नगर निगम की भाजपा सरकार द्वारा सत्ता में आते ही सफाई कर्मचारियों के नियमितीकरण का कार्य तेज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि स्थायी समिति बने अभी कुछ ही हफ्ते हुए हैं और 200 सफाई कर्मचारियों को आज नियमित किया जा रहा है। महज पौने के कहा कि जल्द ही बाकी बचे अस्थायी सफाई कर्मचारियों को भी तेजी से नियमित किया जाएगा। सिंह ने कहा कि सफाई कर्मचारी नगर निगम की रीढ़ हैं। जो दिल्ली को स्वच्छ व स्वस्थ रखने में सबसे अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने कहा कि हमारे सफाई कर्मी हमारे स्वच्छता सैनिक हैं जो शहर को स्वच्छ रखकर सभी नागरिकों की बीमारियों से रक्षा करते हैं।

कमरे के अंदर मिला युवक का शव

नई दिल्ली। सीलमपुर इलाके में उस वक्त हड़कंप मच गया जब गौतमपुरी की गली नंबर 10 स्थित एक घर से दुर्गंध आने की सूचना पुलिस को मिली। घटनादोपहर करीब 2:25 बजे की है जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को शिकायत दी कि एक मकान से तेज दुर्गंध आ रही है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची और पाया कि मकान की दूसरी मंजिल पर स्थित एक कमरा अंदर से बंद था। मामले की गंभीरता को देखते हुए दमकल विभाग को बुलाया गया। दमकल कर्मियों ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कमरे के अंदर एक व्यक्ति का शव सड़ी-गली अवस्था में पड़ा था। पुलिस के मुताबिक जांच में मृतक की पहचान कुपाल सिंह के रूप में हुई है। प्रारंभिक जांच में पता चला है कि कुपाल सिंह अकेले रहते थे और किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। पड़ोसियों ने बताया कि उन्हें पिछले तीन दिनों से नहीं देखा गया था। भाजपा मिलने के बाद क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लेब की टीम को मौके पर बुलाया गया। जिन्होंने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। शव को पोस्टमार्टम के लिए जीटीबी अस्पताल भेजा गया है। पुलिस का कहना है कि मौत के कारणों का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही हो पाएगा। फिलहाल पुलिस सभी पहलुओं से जांच कर रही है।

कांग्रेस के दबाव के चलते सरकार जाति जनगणना कराने पर मजबूर हुई : सप्तगिरि उलाका

नई दिल्ली । केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जाति जनगणना को लेकर अधिसूचना जारी करने के बाद कांग्रेस सांसद सप्तगिरि उलाका ने दावा किया है कि कांग्रेस पार्टी के दबाव के चलते केंद्र सरकार को जाति जनगणना कराने पर मजबूर होना पड़ा है। उन्होंने इसके लिए स्पष्ट समय सीमा की मांग की है। सप्तगिरि उलाका ने समाचार एजेंसी से कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के लगातार दबाव के कारण सरकार जाति जनगणना कराने के लिए मजबूर हुई। हालांकि, हमारी मांग सिर्फ जाति जनगणना की घोषणा के लिए नहीं है, हम एक स्पष्ट समयसीमा, आवंटित बजट का विवरण और जनगणना के संचालन के लिए अपनाए जाने वाले मॉडल के बारे में स्पष्टता चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि जाति का नाम लेकर यह किंगडोम जाए। तेलंगाना में जिस तरह से बातचीत कर मॉडल निकाला गया है, वैसे ही होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे विपक्ष को लेकर इस पर चर्चा करें।बता दें कि यह पहली बार



सके और इन्हें लक्ष्य-आधारित कर सके। सप्तगिरि उलाका ने ओडिशा सरकार के एक साल पूरे होने पर कहा कि अगर एक साल में राज्य में कोई भी काम नहीं किया गया है। लेकिन हर जगह भ्रष्टाकर सरकार विकास मेला कर रही है। राज्य में महिलाओं पर अत्याचार, बेरोजगारी और पलायन बढ़ा है, विकास नहीं। आदिवासी मुख्यमंत्री होने के नाते लोगों को उम्मीद थी कि आदिवासियों की रक्षा करेंगे, लेकिन शोषण बढ़ गया है।

करते हुए कहा कि कांग्रेस यह स्वीकार नहीं कर पा रही है कि पीएम मोदी के कार्यकाल में भारत तेजी से विकास कर रहा है और लगातार आगे बढ़ रहा है। नकवी ने कहा कि भारत आज दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन

भारतीय चाहें तो देश की अर्थव्यवस्था को खुद बहुत बड़ा कर सकते हैं : सीएम रेखा गुप्ता

एजेंसी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। इसमें दिल्ली सरकार के शुरुआती 100 दिनों के कार्यों की झलक भी देखने को मिली। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर भारतीय चाहें तो अपने देश की अर्थव्यवस्था को खुद बहुत बड़ा कर सकते हैं। रेखा गुप्ता ने प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद कहा, आजकल लोगों को विदेशों में जाने का चक्का लगा है, अगर कहीं जाना है तो पहले देश घूमें। पीएम मोदी बहुत भविष्य से देश के लिए काम कर रहे हैं। लोगों को खादी के



अर्थव्यवस्था को खुद बहुत बड़ा कर सकते हैं। उद्घाटन की तस्वीरें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर करते हुए मुख्यमंत्री ने दिल्ली

केन्द्र ने जनगणना से जुड़ी अधिसूचना जारी की

एजेंसी
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने 2027 में होने वाली 16वीं जनगणना के लिए राजपत्र अधिसूचना जारी कर दी है। इस जनगणना में पहली बार जाति गणना भी शामिल होगी। अधिसूचना के अनुसार लद्दाख और जम्मू-कश्मीर के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के केंद्र शासित प्रदेशों में जनगणना 1 अक्टूबर, 2026 की मध्यरात्रि से शुरू होगी, जबकि देश के बाकी हिस्सों में गिनती 1 मार्च, 2027 की मध्यरात्रि से शुरू होगी।अधिसूचना में कहा गया है, *केंद्रीय सरकार, जनगणना अधिनियम, 1948 (1948 का 37) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (द्वि), तारीख 28 मार्च, 2019 में प्रकाशित भारत सरकार के गृह मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की अधिसूचना संख्या का.आ. 1455(अ), तारीख 26 मार्च, 2019 के अधिक्रम में उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रम से पहले किया गया है या करने का लोच किया गया है. यह घोषणा करती है कि भारत की जनसंख्या की जनगणना वर्ष 2027 के दौरान की जाएगी। अधिसूचना में कहा गया है, जनगणना के लिए संदर्भ तारीख, संघ राज्य क्षेत्र

लद्दाख के और जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढिरे असमकालिक क्षेत्रों के सिवाय, मार्च, 2027 के पहले दिन के 00:00 बजे होगी। अधिसूचना में कहा गया है, 'संघ राज्य क्षेत्र लद्दाख , जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के बर्फ से ढिरे असमकालिक क्षेत्रों के संबंध में, संदर्भ तिथि 1 अक्टूबर, 2026 को 00:00 बजे होगी। अधिसूचना जारी करने से एक दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आगामी जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की थी। जनगणना दो चरणों में की जाएगी। पहले चरण यानी हाउसहोल्डिंग ऑपरेशन (एचएलओ) में प्रत्येक घर की आवासीय स्थिति, संपत्ति और सुविधाओं के बारे में जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना (पीई) में प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी। जनगणना कार्य के लिए लगभग 34 लाख कर्मचारी और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे।

उत्कृष्ट कार्य करने वाली पंचायतों को राष्ट्रपति करेंगी सम्मानित

एजेंसी
भोपाल। राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन-2047 के अंतर्गत विश्व सिकल सेल दिवस 19 जून को बड़वानी में ग्राम पंचायत तलून के खेल स्टेडियम में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु होंगी। साथ ही, राज्यापाल मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल सहित अन्य मंत्री भी कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस अवसर पर कई नवाचारों का शुभारंभ किया जाएगा जिनमें जैनेटिक कार्डसलिंग जागरूकता वीडियो और प्रभावित गर्भवती महिलाओं के लिए व्यापक दिशानिर्देश/मॉड्यूल शामिल हैं। लक्षित आयु वर्ग की शत-प्रतिशत स्क्रീनिंग पूरा करने वाली पंचायतों को सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के एनसीसी निदेशालय के सहयोग से सिकल

सेल मित्र पहल की शुरुआत भी की जायेगी। सिकल सेल मित्र युवा आबादी में जागरूकता के लिए सेवा प्रदाताओं के बीच लैंक के रूप में कार्य करेंगे। जनसंपर्क अधिकारी अंकुश मिश्रा ने बताया कि पूरे प्रदेश में सिकल सेल रोग के प्रति जागरूकता लाने की गतिविधियां आयोजित की जायेंगी। सिकल सेल मंत्रालय (भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय) की जनसंख्या गणना (पीई) में प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी एकत्र की जाएगी। इसके बाद दूसरे चरण यानी जनसंख्या गणना (पीई) में प्रत्येक घर के प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी एकत्र की जाएगी। जनगणना में जाति गणना भी की जाएगी। जनगणना कार्य के लिए लगभग 34 लाख कर्मचारी और पर्यवेक्षक तथा लगभग 1.3 लाख जनगणना पदाधिकारी तैनात किए जाएंगे।

के तरीकों से अवगत कराया जाएगा। प्रभावित जिले की विशेष रूप से प्रभावित जनजातीय एवं ग्रामीण पंचायतों में स्क्रीनिंग और परामर्श के लिए अभियान चलाया जाएगा। राज्य स्तर पर विकसित जैनेटिक कार्डसलिंग कार्ड का वितरण किया जाएगा, जिससे लोगों को आनुवंशिक जानकारी समझने में सुविधा होगी। दिव्यांता योजनाओं और वित्तीय सहायता से सिकल-सेल रोगियों को जोड़ने की प्रक्रिया सरल करने के लिए यूडीआईडी कार्ड निर्माण के लिए मेगा शिविर भी लगाए जाएंगे। प्रदेश में राष्ट्रीय सिकल सेल उन्मूलन मिशन के अंतर्गत अब तक 1 करोड़ 6 लाख से अधिक नागरिकों की सिकल सेल स्क्रीनिंग की जा चुकी है और इनमें से 2 लाख से अधिक वाहक चिन्हित हुए और 29,277 लोग सिकल सेल रोग से ग्रसित पाए गए। इन मरीजों का उपचार जारी है। अब तक 80 लाख

9 हजार से अधिक सिकल सेल कार्ड वितरित किए जा चुके हैं जिनसे प्रभावित नागरिक अपनी स्वास्थ्य स्थिति को समझ कर उचित उपचार प्राप्त कर रहे हैं। नेशनल सिकल सेल पोर्टल के माध्यम से स्क्रीनिंग व उपचार की सतत मॉनीटरिंग की जा रही है। रोगियों को निःशुल्क उपचार, जैनेटिक कार्डसलिंग, औषधियां, वैक्सीनेशन एवं ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। अब तक 26,11,5 रोगियों को हार्डड्राईसीयूरिया दवा से उपचार मिला है। विभिन्न विभागों के साथ समय-वक़्त कर जनजातीय स्कूलों, कॉलेजों व छात्रावासों में स्क्रीनिंग शिविर भी सतत आयोजित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मिशन की शुरुआत 15 नवंबर 2021 को राज्य हिमोलोबिनोंथी मिशन के रूप में अलीराजपुर और झाबुआ में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में की थी।

चौधरी ब्रह्म प्रकाश का दूरदर्शी नेतृत्व आने वाली पीढ़ियों को सदैव प्रेरित करता रहेगा: विजेंद्र गुप्ता

एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सोमवार को कहा कि *चौधरी ब्रह्म प्रकाश का दूरदर्शी नेतृत्व और उनकी अमर विरासत सदैव प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। उन्होंने यह वक्तव्य दिल्ली विधानसभा परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान दिल्ली के प्रथम मुख्यमंत्री स्व. चौधरी ब्रह्म प्रकाश जी की 107वीं जयंती पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए दिया। इस अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि समारोह में अध्यक्ष गुप्ता के अलावा उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट, लोक निर्माण एवं विधायी कार्य मंत्री परवेश साहिब सिंह, समाज कल्याण, अनुसूचित जाति/जनजाति कल्याण, सहकारिता एवं निर्वाचन मंत्री इन्द्राज सिंह, नगर निगम के उपमहापौर जय भगवान यादव तथा मुख्य सचिव अश्वि वर्मा भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान चौधरी ब्रह्म प्रकाश के जीवन से जुड़ी दुर्लभ और ऐतिहासिक झलकियों की एक विशेष फोटो प्रदर्शनी भी विधानसभा परिसर में लगाई गई। विजेंद्र गुप्ता ने अपने संबोधन में चौधरी ब्रह्म प्रकाश के योगदान को याद करते हुए कहा कि 15 मार्च 1979 को तत्कालीन नेता स्व. साहिब सिंह वर्मा द्वारा दिल्ली विधानसभा परिसर में चौधरी ब्रह्म प्रकाश की प्रतिमा की स्थापना की गई थी, जिसमें पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी भी उपस्थित थे। उन्होंने बताया कि स्व. साहिब सिंह वर्मा स्वयं चौधरी ब्रह्म प्रकाश से गहराई से प्रभावित थे और उन्हें अपना राजनीतिक मार्गदर्शक मानते थे।

जातिगत जनगणना सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम : भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा

एजेंसी
नई दिल्ली। जातिगत जनगणना का गजट नोटिफिकेशन जारी होने पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जमाल सिद्दीकी का कहना है कि मोदी सरकार के जरिए जातिगत जनगणना का निर्णय एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी कदम है। उन्होंने कहा कि जनगणना का फॉर्म भरेते समय मुसलमान अपनी जाति की सही जानकारी दें और कट्टरपंथी मौलानाओं के बहकावे में नहीं आएँ, क्योंकि यह सामाजिक न्याय की दिशा में ठोस कदम है। पहली बार मुस्लिम समुदाय के भीतर मौजूद जातियों की भी विस्तृत गिनती की जाएगी। अब तक मुस्लिमों को केवल एक धार्मिक समूह के रूप में दर्ज किया जाता रहा है, जिससे उनके भीतर की सामाजिक और आर्थिक विविधताओं पर स्पष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इस जनगणना से मुस्लिम समुदाय की



आधार बन सकते हैं। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि पसमांदा मुसलमान मुस्लिम कट्टरपंथियों के बहकावे में न आएँ और अपनी जाति की सही जानकारी उपलब्ध कराएँ क्योंकि कुछ कट्टरपंथी मौलानाओं द्वारा गुमराह करने के लिए लोगों से अपील की जा रही की जातिगत जनगणना के दौरान मुस्लिम

अपनी जाति इस्लाम बताएँ। जबकि यह जातिगत जनगणना है, धार्मिक जनगणना नहीं। जाति संस्कृति का हिस्सा है, धर्म का हिस्सा नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय संस्कृति में जातियां होती हैं जिसके द्वारा मुस्लिम समाज के भीतर भी जातिगत विविधताओं को सामने लाया जाएगा, तो उस एकरूपता की धारणा टूटेगी। इस पहल का सबसे बड़ा असर पसमांदा मुस्लिम समुदाय पर पड़ सकता है। मुस्लिम समाज में भी 85 फीसद जनसंख्या पसमांदा मुसलमानों की है, जो पिछड़े हुए हैं, लेकिन सामाजिक, राजनीतिक क्षेत्र में उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है। लेकिन ठोस आंकड़े नहीं होने के कारण उनकी आवाज अनसुनी कर दी जाती है। देश के सभी मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने का दावा करने वाले आल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड में भी एक भी पसमांदा मुसलमान सदस्य नहीं है।

तेलंगाना मॉडल पर हो जाति जनगणना : इमरान मसूद

एजेंसी
नई दिल्ली । केंद्र सरकार द्वारा जनगणना के लिए अधिसूचना जारी करने के बाद अब देश में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने तेलंगाना मॉडल पर जाति जनगणना कराने की मांग की है और इसके स्पष्ट प्रारूप की वकालत की है। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने सोमवार को समाचार एजेंसी से बातचीत में कहा, अगर जनगणना तेलंगाना के प्रारूप के अनुसार होगी तो यह सार्थक होगी, लेकिन अगर इसे बिहार की तरह किया जाएगा तो यह निरर्थक होगी। इसलिए प्रारूप को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए। तेलंगाना में जनगणना एक व्यापक डोर-टू-डोर सर्वे के रूप में आयोजित की गई, जिसमें राज्य के सभी 33 जिलों को शामिल किया गया। महाराष्ट्र के पुणे में पुल ढहने की घटना पर कांग्रेस सांसद ने कहा,

भ्रष्टाचार स्पष्ट रूप से मौजूद है, भ्रष्टाचार का मुद्दा कहां चला गया? चाहे पुल गिरे या लोग मरें, इस देश में अब कुछ भी मायने नहीं रखता। इतना खराब मौसम होने के बाद हेलीकॉप्टर क्यों उड़या जा रहा था, इसका जवाब कौन देगा? अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, यह बड़ी दुर्घटना थी, लेकिन खराब मौसम में हेलीकॉप्टर उड़ाने का क्या मतलब समझा जाए? साइप्रस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि डिजिटल पेमेंट के मामले में भारत सबसे आगे है। इस पर कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि भारत बेरोजगारी में भी सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि युवाओं को देश की तरक्की के साथ नहीं जोड़ा जा रहा है। देश में 65 प्रतिशत आबादी युवाओं की है और देश के नवजवान परेशान हो रहे हैं, इससे ज्यादा दुखद क्या होगा।

दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने पीएम मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल को बताया ‘युग परिवर्तक’

एजेंसी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के 11 वर्ष और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सोमवार को यहां एक प्रदर्शनी लगाई गई। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की मौजूदगी में इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया गया। वीरेंद्र सचदेवा ने सोमवार को मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि हम पीएम मोदी के 11 वर्ष के कार्यकाल को देखें तो इसमें सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के लिए काम किया गया है। इसे हम सही मायनों में युग परिवर्तन कहते हैं। यह 11 साल प्रगति और भरोसे के हैं। 11 साल के इस स्वर्णिम काल ने भारत को विश्वगुरु बनाने की दिशा में अग्रसर किया है। उन्होंने कहा कि आज जो यह प्रदर्शनी शुरू की गई है, इसे हम दिल्ली की जनता के बीच लेकर जाएंगे। प्रदर्शनी में पीएम मोदी के 11 साल और दिल्ली सरकार के 100



बताएंगे। दिल्ली के अलग-अलग जिलों में यह प्रदर्शनी लगाई जाएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने केंद्र सरकार के 11 साल और दिल्ली सरकार के 100 दिन पूरे करने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि दिल्ली में *डबल इंजन सरकार+ ने जिस तरह से काम करना शुरू किया है, वह सराहनीय है। केंद्र ने हमेशा दिल्ली के लिए

काम किया है, लेकिन दुर्भाग्य से पिछली सरकार ने न तो उनके प्रयासों को पहचाना और न ही उन्हें श्रेय दिया। आज जब हम दिल्ली को देखते हैं, तो हम देख सकते हैं कि

हमें बेहतरीन बुनियादी ढांचे के विकास में केंद्र से महत्वपूर्ण सहयोग मिला है। हरदीप सिंह पुरी ने भी पीएम मोदी के 11 साल के कार्यकाल के सराहा। उन्होंने कहा कि हमें अब विकास के वादों को पूरा करना चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि दिल्ली को वह मिले जिसकी वह हकदार है।

कांग्रेस को न तो विदेश नीति समझ में आती है और न ही राष्ट्रहित : मुख्तार अब्बास नकवी

बढ़ रही है और इसके लिए हमें उनसे अनुमोदन के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग हैं, जिन्होंने अपने परिवार की ज़िम्मेदारिताओं के आधार पर विदेश नीति को आकार देने की कोशिश की। उनके लिए राष्ट्रहित महत्वपूर्ण

है। यह स्पष्ट कर दूँ कि प्रधानमंत्री सिर्फ एक राजनीतिक दल के नहीं और भ्रम पैदा करने की कोशिश वह हमेशा देश के हितों को सर्वोपरि रखते हुए प्राथमिकता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। नकवी ने आगे कहा कि हमेशा से यह परंपरा रही है कि जब

प्रधानमंत्री या कोई राष्ट्रीय नेता विदेश में हैं, तो देश के भीतर भय और भ्रम पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। लेकिन, कांग्रेस अपनी कृत्यों से बाज नहीं आ रही है। भारत की जनता कांग्रेस का असली चेहरा देख रही है।

एजेंसी
नई दिल्ली । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की साइप्रस यात्रा को कांग्रेस की ओर से इवेंट बताए जाने पर भाजपा भड़क गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के बयान पर पलटवार

किया है। कांग्रेस को यह स्वीकार करना चाहिए कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश लगातार आगे बढ़ रहा है।मुख्तार अब्बास नकवी ने सोमवार को समाचार एजेंसी आईएनएसएस से बातचीत की। उन्होंने बातचीत के दौरान कांग्रेस

पर हमला करते हुए कहा कि कुटिल कटुता के कबाइखाने में फंसी कांग्रेस पार्टी को न तो विदेश नीति समझ में आती है और न ही राष्ट्रहित। हमारी विदेश नीति राष्ट्रीय हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए निरंतरता बनाए रखते हुए आगे

बढ़ रही है और इसके लिए हमें उनसे अनुमोदन के प्रमाणपत्र की आवश्यकता नहीं है। ये वही लोग हैं, जिन्होंने अपने परिवार की ज़िम्मेदारिताओं के आधार पर विदेश नीति को आकार देने की कोशिश की। उनके लिए राष्ट्रहित महत्वपूर्ण

संपादक की कलम से

एक ही झूठ को बार बार दोहराने से वह सच नहीं हो जाता

यह काफी पुरानी कहावत है कि एक झूठ को सौ बार बोला जाए तो वह सच लगने लगता है। सोशल मीडिया के जमाने में यह बात और भी सही साबित हो रही है। फर्जी खबरों से परेशान होकर गुगल और फेसबुक ने वादा किया है कि वे इस समस्या से निपटने के प्रयास कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि क्या यह वाकई एक समस्या है और क्या लोग वाकई इतने भोले-भाले होते हैं कि झूठ को बार-बार बोलने से उस पर यकीन करने लगे?

कुछ अध्ययनों से तो लगता है कि सचमुच ऐसा ही होता है। यू.एस. के एक पत्रकार क्रेग सिल्वरमैन ने कुछ ऑनलाइन झूठी खबरों का विश्लेषण करने पर पाया कि झूठी खबरों को ज्यादा तवज्जो मिलती है बनिस्वत उन आलेखों के जो इन खबरों का पदार्फाश करने की कोशिश करते हैं। शायद आपको लगे कि आप ऐसी झूठी खबरों के जाल में नहीं फँस सकते। मगर 1940 में किए गए एक अध्ययन का निष्कर्ष था कि हूकॉई अफवाह जितनी ज्यादा बार कही जाए, वह उतनी ही संभव लगने लगती है। इसका मतलब है कि कोई झूठ सिर्फ प्रसार के दम पर लोगों के विचारों और अभिमतों को प्रभावित कर सकती है।

इसके बाद 1977 में एक और अध्ययन ने इसी बात को थोड़ा अलग ढंग से प्रस्तुत किया था। यूएस के कुछ शोधकर्ताओं ने कॉलेज के विद्यार्थियों से किसी वक्तव्य की प्रामाणिकता को लेकर पूछताछ की। उन्हें बताया गया था कि वह वक्तव्य सही भी हो सकता है और गलत भी। शोधकर्ताओं ने पाया कि यदि उसी वक्तव्य को कुछ दिनों बाद फिर से दोहराया जाए तो इस बात की संभावना बढ़ती है कि विद्यार्थी उस पर यकीन करने लगेंगे।

वर्ष 2015 में वान्दरविल्ट विश्वविद्यालय (टेनेसी) की लिजा फेजियो ने एक अध्ययन में देखा कि चाहे विद्यार्थी जानते हों कि कौन कथन गलत है, मगर यदि उसे दोहराया जाए, तो काफी संभावना बनती है कि वे उस पर विश्वास कर लेंगे। फेजियो का कहना है कि झूठी खबरें लोगों को तब भी प्रभावित कर सकती हैं जब वे जानते हैं कि वह झूठी है। वही खबर या वही सुर्खियां बार-बार पढ़ने पर लगने लगता है कि शायद वह सच है। लोग प्रायः जांच करने की कोशिश भी नहीं करते। मसलन, हाल में किए गए एक अध्ययन में यूएस के हाई स्कूल छात्रों को एक तस्वीर दिखाई थी। इसमें बताया गया था कि दुर्घटना के बाद फुकुशिमा दायी परमाणु बिजली घर के आसपास पौधों पर विकृत फूल उग रहे हैं। जब यह पूछा गया कि क्या वह तस्वीर बिजली घर के आसपास की स्थिति का प्रमाण माना जा सकता है, तो मात्र 20 प्रतिशत छात्रों ने ही इस पर शंका जाहिर की जबकि 40 प्रतिशत ने तो माना कि यह स्पष्ट प्रमाण है। तस्वीर के साथ यह नहीं बताया गया था इसे प्रस्तुत किसने किया है।

कुछ अध्ययनों से यह भी पता चला है कि आजकल लोग सच ईजिन्य पर काफी भरोसा करते हैं और उसमें भी जो पहली प्रविष्टि होती है उसे ही सच मान लेते हैं।

ऐसी स्थिति में आलोचनात्मक सोच विकसित करने का महत्व बहुत बढ़ जाता है अन्यथा हम झूठ और सच का फैसला किए बगैर अफवाहों के जाल में हाथ-पांव मारते रहेंगे।

हिटलर के युद्ध विशेषज्ञ गोएबल्स ने भी यही दर्शन इस्तेमाल किया था। इसलिए हिटलर जीत नहीं पाया, लेकिन हिटलर के बयान में सच्चाई लंग रही थी। राहुल गांधी के बारे में भी यही बात कही जा सकती है। राहुल गांधी एक ही बात को बार-बार झूठ बोलने के आदी हो गए हैं और वह हर चुनाव हार जाते हैं और अभी भी भाजपा के खिलाफ आरोप लगाते रहते हैं। लेकिन वे किसी काम के नहीं हैं और लोग हंसते हैं। राहुल ने ताजा आरोपों में भाजपा पर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि भाजपा ने हाल के चुनावों में एक बड़ा धोखा किया है और उन्होंने इसे उजागर करने का नाटक किया है। लेकिन चुनाव आयोग ने पारस्परिक रूप से उन पर आरोप लगाया है और दिखाया है कि उनके आरोप कितने झूठे और हास्यास्पद हैं। भाजपा अध्यक्ष जे पी नड्डा ने राहुल को जवाब दिया है और वो भी अपने अंदाज में। उन्होंने कहा कि राहुल द्वारा अपने नवीनतम लेख में लगाए गए आरोप उनके फर्जी नैटिव का एक अकाउंट है। यह इस बात का संकेत है कि आगामी बिहार चुनाव में कांग्रेस और उसके सहयोगी दल किस तरह निराश होंगे। उन्होंने राहुल के हर फर्जी नैटिव पर नकेल कसी है और उनके द्वारा उठाए गए हर बिंदु का जवाब दिया है।

कांग्रेस चुनाव दर चुनाव हार रही है और हर बार कांग्रेस पार्टी किसी और को जिम्मेदार ठहराने के बजाय उसे जिम्मेदार ठहरा रही है। भारत की जनता ने इसे कई बार देखा है। लेकिन जेपी नड्डा को जाने दो। वह एक प्रतिद्वंद्वी है, लेकिन चुनाव आयोग ने खुद राहुल के आरोपों को निराधार बताया है और आयोग किसी का गुलाम नहीं है। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि क्या राहुल गांधी भाजपा के खिलाफ अपने आरोपों को स्वीकार करेंगे। आयोग ने खुद आरोपों से इनकार किया है। सवाल ये है कि क्या राहुल अपनी बात मर्निंगे या फिर वो ये भी कहेंगे कि वे भी विपक्ष का खेल है, यानी कांग्रेस विपक्ष का। राहुल गांधी के पास लोगों को देने के लिए कोई आकर्षक कार्यक्रम और कोई घोषणा नहीं है। उनके पास लोगों को बनाए रखने की कोई योजना नहीं है। कांग्रेस के पास पैसा नहीं है। नेताओं के पास बहुत पैसा है लेकिन पार्टी के पास एक रुपया भी नहीं है। उनके पास पार्टी के कार्यक्रम के बिलों का भुगतान करने के लिए भी पैसा नहीं है। ऐसे में राहुल बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, जो उनके हौसले की पराकाष्ठा है।

सिर में दर्द माइग्रेन का है तो जरूर दिखते हैं ये लक्षण,

आजकल भागदौड़ भरी जिंदगी में सिर दर्द आम समस्या बन गई है, लेकिन अगर ये दर्द बार-बार हो रहा है या एक तरफा हो रहा है तो इसे हल्के में लेना अनुमानदायक हो सकता है. कई बार लोग इसे सामान्य सिर दर्द समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि ये माइग्रेन हो सकता है. माइग्रेन एक न्यूरोलॉजिकल समस्या है, जो दिमाग में असंतुलन और नसों में सूजन के कारण होती है. डॉक्टरों के मुताबिक माइग्रेन के सिरदर्द में कुछ खास लक्षण नजर आते हैं, जिनकी पहचान करना जरूरी है ताकि सही समय पर इलाज मिल सके.

दिल्ली के जीबी पंत अस्पताल में न्यूरोसर्जरी विभाग में डॉ. दलजीत सिंह बताते हैं किमाइग्रेन का सिर दर्द सामान्य सिर दर्द से अलग होता है. इसमें दर्द सिर के एक तरफ ज्यादा महसूस होता है. कई बार ये दर्द धीरे-धीरे शुरू होता है और कुछ घंटों या दिनों तक बना रह सकता है. माइग्रेन में सिर में तेज धड़कन जैसा दर्द महसूस होता है, जो काम करने की क्षमता को भी प्रभावित करता है. खास बात ये कि माइग्रेन का दर्द बिना किसी कारण के अचानक भी शुरू हो सकता है.

माइग्रेन के मुख्य लक्षण

माइग्रेन सिर दर्द के साथ कई और लक्षण भी लेकर आता है. डॉक्टरों ने कुछ ऐसे संकेत बताए हैं जिनसे आप समझ सकते हैं कि सिर दर्द सामान्य नहीं बल्कि माइग्रेन का है. अक्सर माइग्रेन में सिर के एक ही तरफ तेज दर्द होता है. कुछ लोगों में ये दर्द बारी-बारी से सिर के दोनों तरफ भी हो सकता है.

„तेज रोशनी और आवाज से परेशानी

„माइग्रेन के दौरान तेज रोशनी या तेज आवाज बर्दाश्त नहीं होती. मरीज को शांत और अंधेरे कमरे में आराम करने की जरूरत महसूस होती है.

„माली और उल्टी आना

„सिर दर्द के साथ-साथ मितली महसूस होना या उल्टी होना माइग्रेन का आम लक्षण है.

„धुंधला दिखना

जनगणना की मांग करने वाले दलों को अब मिलेगी शांति पर इसका दूसरा पहलू भी गौरतलब है

अशोक भाटिया , मुंबई

जनगणना की मांग करने वाले दलों के लिए अब राहत की खबर है। केंद्र सरकार देश में जाति जनगणना का एलान तो पहले ही कर चुकी है। अब सरकार ने तारीखों का भी एलान कर दिया है। सुत्रों की मुताबिक, भारत में 1 अक्टूबर 2026 से जाति गणना के साथ जनगणना शुरू होगी। यह जनगणना देशभर में दो चरणों में कराई जाएगी। बता दें कि, जनगणना 1951 से प्रत्येक 10 साल के अंतराल पर की जाती थी (2021 में कोरोना महामारी के कारण टली)। जनगणना के आंकड़े सरकार के लिए नीति बनाने और उन पर अमल करने के साथ-साथ देश के संसाधनों का समान वितरण सुनिश्चित करने के लिए बेहद अहम होते हैं। वहीं राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर) को भी अपडेट करने का काम बाकी है। सुत्रों के मुताबिक, 16 जून 2025 को जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत अधिसूचना जारी होने ही यह प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो जाएगी। इसके बाद जनगणना से जुड़ी विभिन्न एजेंसियां सक्रिय हो जाएंगी। पहले चरण में स्टाफ की नियुक्ति, प्रशिक्षण, जनगणना फॉर्मेट तैयार करना और फील्ड वर्क की योजना बनाई जाएगी। खास बात यह है कि इस बार जनगणना और जातिगत जनगणना एक साथ की जाएगी। इसके बाद चरणों में पूरी होगी। पहला चरण 1 फरवरी 2027 तक पूरा किया जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम चरण फरवरी 2027 के अंत तक संपन्न होगा। 1 मार्च 2027 की मध्याह्न को संदर्भ तिथि माना जाएगा, यानी उस समय देश की जनसंख्या और सामाजिक स्थिति का जो भी आंकड़ा होगा, वही रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा। इस दिन के बाद से आंकड़े सार्वजनिक रूप से सामने आने लगेंगे। यह ऐतिहासिक कदम देश की सामाजिक संरचना को बेहतर ढंग से समझने और नीतिगत फैसलों के लिए मजबूत आधार प्रदान करेगा।

वहीं हिमालयी और विशेष भौगोलिक परिस्थितियों वाले राज्य जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और



उत्तराखंड में यह जनगणना प्रक्रिया अन्य राज्यों से पहले, अक्टूबर 2026 तक पूरी कर ली जाएगी। वहां मौसम की कठिनाइयों और दुर्गम क्षेत्रों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 के तहत, 1 मार्च 2027 को जनगणना की संदर्भ तिथि घोषित की जाएगी और संबंधित अधिसूचना 16 जून 2025 को राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी। इसके बाद जनगणना की आधिकारिक तैयारियां प्रारंभ हो जाएंगी।

बता दें कि इस बड़े फैसले की पृष्ठभूमि में अप्रैल में केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव की ओर से की गई घोषणा थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि कैबिनेट की राजनीतिक मामलों की समिति ने आगामी जनगणना में जातिगत आंकड़ों को शामिल करने की स्वीकृति दे दी है।उन्होंने कहा था, हूकैबिनेट समिति ने आगामी जनगणना में जातिगत गणना को शामिल करने का निर्णय लिया है। यह फैसला सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण तथा समग्र राष्ट्रीय प्रगति की दिशा में एक अहम कदम है।इन्होंने यह भी आश्वासन दिया कि जनगणना पारदर्शी तरीके से कराई जाएगी।

देशभर में जातिगत गणना की मांग काफी समय से उठती रही थी । कांग्रेस, कटऊकअ गठबंधन और विभिन्न क्षेत्रीय दलों ने बार-बार इसकी आवश्यकता को रेखांकित करती रही है। हाल ही में कांग्रेस

शासित कर्नाटक सरकार ने राज्य स्तरीय जातिगत सर्वे कराया था, जिसे लेकर कुछ प्रमुख समुदायों वोक्कालिगा और लिंगायत ने इस कहते हुए आपत्ति जताई थी कि इस सर्वे में उनके साथ न्याय नहीं हुआ। गौरतलब है कि भारत में यह जनगणना मूल रूप से अप्रैल 2020 में आयोजित की जानी थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था। अगर इसे तब समय पर किया गया होता, तो अंतिम रिपोर्ट 2021 तक सामने आ जाती।जनगणना 2027 सिर्फ जनसंख्या की गणना भर नहीं होगी, बल्कि यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। वंचित वर्गों की सही पहचान और उनके लिए योजनाओं की बेहतर दिशा तय हो सकेगी। आरक्षण व्यवस्था और सामाजिक न्याय से जुड़े मुद्दों पर तथ्यात्मक और अद्यतन आंकड़े उपलब्ध होंगे। नीतियों और योजनाओं का पुनर्गठन संभव होगा जो समावेशी विकास की दिशा में उपयोगी हो सकता है। भारत में पिछली जनगणना वर्ष 2011 में की गई थी, जो दो चरणों में पूरी हुई थी। पहला चरण मकान सूचीकरण (लखड) और दूसरा चरण जनगणना (ढए)। 2021 में आगामी जनगणना प्रस्तावित थी, जिसकी सभी तैयारियां भी पूरी हो गई थीं, लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित करना पड़ा। यदि यह जनगणना

समय पर होती, तो 2021 तक इसकी अंतिम रिपोर्ट सामने आ चुकी होती। गुह मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक्स पर पोस्ट किया, हूजनगणना 2021 के लिए सभी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं। हालाँकि, पूरे देश में कोविड के प्रकोप के कारण जनगणना का काम स्थगित कर दिया गया था। कोविड ने शिक्षा सहित सभी क्षेत्रों को बाधित किया। जनगणना के लिए लगभग 30 लाख गणनाकर्ताओं की आवश्यकता है और उनमें से अधिकांश प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक हैं। कोविड के बाद जनगणना प्राथमिक शिक्षा को बाधित कर सकता था।हू प्रवक्ता ने कहा कि जिन देशों ने महामारी के तुरंत बाद जनगणना की उन्हें जनगणना के आंकड़ों की कवरेज पर समस्याओं का सामना करना पड़ा। केंद्र की प्रतिबद्धता दोहराते हुए प्रवक्ता ने कहा कि जनगणना प्रक्रिया अब तुरंत शुरू होगी और 1 मार्च, 2027 को संदर्भ तिथि के रूप में समाप्त होगी। पोस्ट में कहा गया है, हू जनगणना के संचालन के लिए बजट कभी भी बाधा नहीं रहा है क्योंकि सरकार द्वारा हमेशा धन का आवंटन सुनिश्चित किया जाता है। गुह मंत्रालय बताया कि, "जातियों की गणना के साथ-साथ दो चरणों में जनसंख्या जनगणना-2027 आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। जनसंख्या जनगणना-2027 के लिए संदर्भ तिथि मार्च,

2027 के पहले दिन 00:00 बजे होगी। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के गैर-समकालिक बफरलैंड क्षेत्रों के लिए, संदर्भ तिथि अक्टूबर, 2026 के पहले दिन 00।00 बजे होगी। उपरोक्त संदर्भ तिथियों के साथ जनसंख्या जनगणना आयोजित करने के इरादे की अधिसूचना जनगणना अधिनियम 1948 की धारा 3 के प्रावधान के अनुसार 16।06।2025 को आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।" भारत में हर दस साल में जनगणना होती है। पहली जनगणना 1872 में हुई थी। 1947 में आजादी मिलने के बाद पहली जनगणना 1951 में हुई थी और आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी। आंकड़ों के मुताबिक, 2011 में भारत की कुल जनसंख्या 121 करोड़ थी, जबकि लिंगानुपात 940 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष और साक्षरता दर 74।04 फीसदी था। ज्ञात हो कि देश में जनगणना की शुरुआत 1881 में हुई थी। पहली बार हुई जनगणना में जातिगत जनगणना के आंकड़े जारी हुए थे। इसके बाद हर दस साल पर जनगणना होती रही। 1931 तक की जनगणना में हर बार जातिवार आंकड़े भी जारी किए गए। 1941 की जनगणना में जातिवार आंकड़े जुटाए गए थे, लेकिन इन्हें जारी नहीं किया गया। आजादी के बाद से हर बार की जनगणना में सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ही जाति आधारित आंकड़े जारी किए। अन्य जातियों के जातिवार आंकड़े 1931 के बाद कभी प्रकाशित नहीं किए गए। जातीय जनगणना का एक दूसरा पहलू भी है जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता । जाति जनगणना का मतलब ही है कि भविष्य में आरक्षण का दायरा बढ़ाया जाएगा। लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जाति जनगणना कराने की घोषणा होने के बाद ही डिमांड रख दी है कि जाति जनगणना का मतलब तभी पूरा होगा जब आरक्षण के 50 प्रतिशत वाले कैप को भी सरकार खत्म

करे। ताकि पिछड़ों को आरक्षण 60, 70, 80 से 90 प्रतिशत तक बढ़ाया जा सके। मंडलवादी पार्टियों की इन्हीं नीतियों के चलते ही देश 1990 से 2000 तक ऐसा अस्थिर हुआ कि एक मजबूत सरकार देश को नसीब नहीं हुई। उस एक दशक में भारत अपने बराबर के देशों जैसे चीन आदि से दशकों पीछे हो गया था। राजनीतिक अस्थिरता ऐसी रही कि देश भ्रष्टाचार और आतंकवाद के काले साए में समाया रहा। जाहिर है कि एक बार फिर वही कहानी दुहराए जाने का अंदेश जताया जा रहा है। क्योंकि अब तो मंडलवादी पार्टियां और कांग्रेस दोनों ही इस मुद्दे पर एक हो गई हैं। जाहिर है कि समस्या और गंभीर होने वाली है। भारत में जाति एक संवेदनशील मुद्दा रहा है। जनगणना में शामिल करने से जातिगत पहचान को और मजबूती मिलने की आशंका है। जाति जनगणना के बाद डइउ, रउ, और रळ की सटीक आबादी और उनकी स्थिति का पता चलेगा। 1990 में केवल अगड़ों ने संघर्ष किया था। पर अब दलित-आदिवासी और ईबीसी जातियां भी आंदोलनकारी होंगी। बहुत सी ऐसी जातियां हैं जो बहुत पिछड़ी हैं पर वो संख्या बल में कमजोर हैं। उनके साथ कैसे न्याय होगा, यह विचारणीय है। जाहिर है कि पिछड़ी जातियों में ही खींचतान बढ़ेगी। लोग मरने मारने पर उतारू होंगे। उच्च जातियों में भी यह डर पैदा हो सकता है कि उनकी हिस्सेदारी कम होगी। जाहिर इसके चलते एक बार फिर अगड़ा बनाम पिछड़ा वर्ग का तनाव बढ़ेगा। जैसा कि 1990 में भी देखा गया था। 1990 में तनाव जल्दी ही शांत हो गया था। इसका कारण था कि लोगों को अपना संख्या बल नहीं पता था। इस बार संघर्ष होगा तो रुकने का नाम नहीं लेगा। पर फिल्मकार विवेक अग्निहोत्री लिखते हैं कि जाति जनगणना जातिवाद को संस्थागत करेगा और सामाजिक एकता को कमजोर करेगा। 1990 में मंडल आयोग की सिफारिशों के बिफरन्यून के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों और सामाजिक तनाव इसका उदाहरण हैं। अशोक भाटिया,

मुंबई में लोकल ट्रेन से गिरकर यात्रियों की मौत को रोकना जरूरी

अभी हाल ही में मुंबई के उपनगर दिवा और मुंन्ना के बीच भीड़ भरी लोकल ट्रेन के दरवाजे पर खड़े कुछ यात्री नीचे गिर गए और कुछ की मौत हो गई और अन्य घायल हो गए। सोमवार को सप्ताह का पहला दिन था जिस दिन मुंबई में उपनगरीय ट्रेनें भीड़ के साथ चलती हैं। मध्य रेलवे के मुंन्ना स्टेशन के पास दो लोकल ट्रेनों के दरवाजे पर खड़े यात्रियों को एक-दूसरे के खिलाफ रगड़ दिया गया। शुरुआत में बताया गया था कि कुछ लोग नीचे गिर गए और हादसा हो गया। इस बात की भी कोई जानकारी नहीं है कि कितने लोग मारे गए या कितने घायल हुए। दुनिया में कहीं भी इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को ले जाने की क्षमता नहीं होनी चाहिए। रात में चार घंटे को छोड़कर, सीएसटी-चचेगेट से कर्जत, कसार, खोपोली, पनवेल और विरार , पालघर, दहानू तक लोकल ट्रेनें चलती हैं।मोनो मुंबईकरों के लिए एक आवश्यक सेवा बन गई है। लोकल ट्रेनें और मेट्रो मुंबईकरों की सांस हैं। फिर, जिस प्रकार इस सेवा को तैयार रखना और चौबीसों घंटे कार्य करना रेलवे के लिए एक चुनौती है, उसी प्रकार यह रेलवे का भी कर्तव्य है। इसी महामुंबई से देश के खजाने में सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। इसी महानगर से देश को सबसे ज्यादा जीएसटी मिल रहा है। बदले में, रेल मंत्रालय भारी राजस्व चुकाने के बाद भी मुंबईकरों की दैनिक स्थानीय यात्रा को आरामदायक बनाने के लिए गणप्य सेवाएं प्रदान करता है?

गौरतलब है कि दादर, कुर्ला, घाटकोपर, ठाणे, कलवा, डॉबिवली, कल्याण और अंधेरी, मध्य और पश्चिम रेलवे के वसई-विवार स्टेशनों पर हमेशा भीड़ रहती है। सीएसटी से कर्जत, कसार, खोपोली, पनवेल आने और जाने वाली लोकल ट्रेनों में हमेशा भीड़ रहती है। इससे भी बदतर, लोकल ट्रेन में यात्रियों की हालत बदतर है। जब कासरा से सीएसटी और सीएसटी से कसार जाने वाली ट्रेन गुजर रही थी, तो जो लोग दरवाजे पर खड़े थे और एक-दूसरे से चिपके हुए थे, उन्हें रगड़ा गया और उनमें से दर्जनों नीचे गिर गए।दिड़ते हुए लोकल में यात्री अपना संतुलन भी नहीं बना पाए, अन्य लोग नीचे गिर लोगों को पकड़ या खींच कर वापस कोच में

नहीं ला सके। कितने लोग घायल हुए, जिनके हाथ-पैर टूटे, किसने अपनी जान गंवाई, इसका विवरण बाद में आएगा, लेकिन भीड़ भरे लोकल के यात्री एक-दूसरे से रगड़कर नीचे गिर गए। यह समय उन पर क्यों आया? कौन जिम्मेदार है? इसका जवाब कोई नहीं देगा। देश में हर जगह वंदे भारत एक्सप्रेस शुरू की जा रही है। वंदे भारत ट्रेन का क्रेज बढ़ रहा है, लेकिन मुंबई के इलाकों में रोजाना यात्रा करने वाले लाखों यात्री हवा में उड़ गए हैं। हर दिन, लाखों मुंबईकर काम तक पहुंचने के लिए भीड़-भाड़ वाले इलाकों में ढाई घंटे की यात्रा कर रहे हैं और आजीविका और रोजगार के लिए एक ही भीड़ से शाम और रात घर लौट रहे होते हैं। बताया जाता है कि मुंबई में लोकल ट्रेन में रोजाना करीब 75 लाख लोग सफर करते हैं. सेंट्रल रेलवे मुंबई उपनगरीय में 1810 ट्रेनों का संचालन करता है, जिसमें प्रतिदिन 70 लाख पैसेंजर सफर करते हैं. वहीं वेस्टर्न उपनगरीय 1394 ट्रेनों का संचालन करता है, जिसमें 35 लाख पैसेंजर सफर करते हैं. एक तरफ जहां लाखों की संख्या में यात्री ट्रेनों में सफर करते हैं, उसी तरह हजारों लोगों की मौत भी ट्रेन की घटनाओं में हुई है. मुंबई हाईकोर्ट में दाखिल जवाब के मुताबिक, पिछले 20 सालों में मुंबई में रेल हादसों में 51,802 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में ट्रेन हादसों में हर दिन सात से आठ लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन उनकी कोई खबर नहीं आती। मुंबई की उपनगरीय रेलवे 'हर दिन कौन रोता है' की स्थिति में है। नए साल 2025 के जनवरी से मार्च के तीन महीनों में मुंबई में ट्रेन हादसों में 663 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 272 की मौत लोकल ट्रेन से गिरने से हुई, जबकि 391 की मौत रेलवे ट्रेक पर करते समय हुई। यह शायद पहली बार हो जब दो लोकल ट्रेनों के यात्री एक-दूसरे पर गिरकर मर गए हों या घायल हुए हों। क्या मुंबई में स्थानीय यात्रा पर किसी का नियंत्रण है? हर ट्रेन में हर लोकल के डिब्बे में बिना टिकट के कई यात्री होते हैं।

सवाल यह है कि भीड़ का दुष्प्रक्र कब खत्म होगा? स्थानीय यात्रियों के लिए कब है राहत? मुंबईकरों को लोकल ट्रेनों में आराम से यात्रा करने का मौका कब मिलेगा? आम लोग शौक के रूप में स्थानीय यात्रा नहीं करते हैं। लाखों लोग स्थानीय यात्रा की ओर आकर्षित होते हैं क्योंकि वे सस्ते और तेज यात्रा कर सकते हैं। पिछले दो वर्षों में वातानुकूलित स्थानों ने चलाना शुरू कर दिया है। जैसे-जैसे उनकी संख्या बढ़ रही है, गैर-एसी स्थान कम हो रहे हैं। मुंबई में, एसी स्थानों की बहुत मांग है। रेल प्रशासन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए।फरट क्लास कोच में भी बिना टिकट के लोगों की भारी भीड़ होती है, यहां तक कि महिलाओं की भी। उन्हें यकीन है कि उनसे टिकट मांगने की कोई नहीं आएगा। बिना टिकट वाले यात्री पास धारकों के लिए रोज की परेशानी बनाए हुए हैं, लेकिन रनिंग लोकल में कोच में आकर टिकट चेकिंग लगभग बंद हो गई है। गंदे पोखर लगाकर बॉसस को साफ करने का नाटक करने वाले लोगों की भारी भीड़ है। हाथों में बच्चा लेकर भीख मांगने वाले भी बड़ी संख्या में लोग हैं। ये सभी लोकल स्टेशन कैसे पहुंच सकते हैं, लोकल में कैसे चढ़ सकते हैं? वह सिस्टम कहाँ है जो उन्हें रोकता है, हटाता है और कार्रवाई करता है। पर्स बीनने वालों और मोबाइल चोरों के गिरोह भी भीड़ में सुराग तलाश रहे हैं। लेकिन जहां उन्हें रेलवे पुलिस का डर नहीं दिखता। दर्जनों यात्री इसलिए गिर गए क्योंकि वे मुंन्ना में भीड़ को संतुलित नहीं कर पाए, अगर इस भीड़ को नियंत्रित नहीं किया गया तो ऐसे हादसे होते रहेंगे। मुंबई की लाइफलान्ड सुरक्षित है।

वैसे बताया जाता है कि मुंबई लोकल में सोमवार को हुए हादसे के बाद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और रेलवे बोर्ड के अधिकारियों ने चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (कउम्ट्रे) टीम के साथ इमरजेंसी मीटिंग की। इसमें मुंबई के लिए अब जो भी नॉन एसी लोकल ट्रेन आएंगी। उन सभी में दिल्ली मेट्रो की तरह ऑटोमेटिक गेट लागू जाएंगे। साथ ही मौजूदा समय में चल रही लोकल के गेटों को स्वचालित गेटों से बदला जाएगा। लेकिन मीटिंग में एक बात यह भी सामने आई कि अगर मुंबई लोकल की नॉन एसी ट्रेनों में ऑटोमेटिक गेट लगा दिए गए तो अंदर डिब्बों में घुटन अधिक हो जाएगी।

धरती पर हर छठा इंसान भारतीय, 77 साल बाद 300 करोड़ हो जाएगी देश की आबादी

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत जनसंख्या के मामले में सभी देशों से आगे निकल गया है और अगले 40 वर्षों में जनसंख्या 170 करोड़ तक पहुंचने की उम्मीद है। यूएनएफपीए की 2025 स्टेट ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन (एसओडब्ल्यूपी) रिपोर्ट में जनसंख्या और प्रजनन क्षमता को लेकर रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट का शीर्षक "द रिथल फर्टिलिटी क्राइसिस" है। इसमें भारत की घटती प्रजनन दर पर चिंता व्यक्त की गई है। इस तरह से ये आंकड़े इस बात पर जोर देते हैं कि लाखों व्यक्ति अपनी वास्तविक प्रजनन आकांक्षाओं को हासिल करने में असमर्थ हैं।मंगलवार को जारी संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष (यूएनएफपीए) की 2025 विश्व जनसंख्या स्थिति रिपोर्ट में कहा गया है कि अब से 40 साल बाद जनसंख्या में गिरावट शुरू होने से पहले लगभग 1.7 बिलियन तक बढ़ने की उम्मीद है। वहीं इस साल चीन की आबादी 1.41 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।बिते वर्ष जुलाई में जारी संयुक्त राष्ट्र की एक अन्य रिपोर्ट विश्व जनसंख्या संभावना-2024 के मुताबिक, पिछले वर्ष भारत की जनसंख्या 1.44 अरब थी।रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की कुल प्रजनन दर घटकर 1.9 हो गई है, जो कि प्रति महिला 2।11 जन्मों की प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्षमता से भी कम है। इसका मतलब ये है कि महिलाएं एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जनसंख्या को बनाए रखने के लिए आवश्यक से कम बच्चे पैदा कर रही हैं।

गौर करें तो जन्म दर में गिरावट के बावजूद, भारत की युवा आबादी काफी बड़ी है। इसमें 24% 0-14 वर्ष की आयु के हैं। 17% 10-19 वर्ष की आयु के हैं। और 26% 10-24 वर्ष की आयु वर्ग के हैं। इसके अतिरिक्त, 68% आबादी कामकाजी आयु (15-64) की है। ये संभावित जनसांख्यिकीय लाभांश प्रस्तुत करती है। बल्लि पर्णार्प रोजगार और इसको सपोर्ट करती हुई नीतियां बनें।मौजूदा समय में बुजुर्ग आबादी (65 वर्ष और उससे ज्यादा) 7% है। आने वाले दशकों में जीवन प्रत्याशा में सुधार के साथ इस आंकड़ों में वृद्धि होने की उम्मीद है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट कहती है कि 2025 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा पुरुषों के लिए 71 वर्ष और महिलाओं के लिए 74 वर्ष होने का अनुमान है।इन आंकड़ों के पीछे उन लाखों दम्पतियों की कहानियां हैं, जिन्होंने अपना परिवार शुरू करने या बढ़ाने का निर्णय लिया है। साथ ही उन महिलाओं के अनुभव भी हैं जिनके पास गर्भधारण करने के संबंध में सीमित विकल्प थे, चाहे वे कब, कितनी बार या गर्भवती हों। यह भी बताया जाता है कि अगले 40 वर्षों में 240 मिलियन और जुड़ जाएगी और फिर भारत की जनसंख्या पहले बस जाएगी और फिर कुछ हद तक घट जाएगी। यह सिर्फ आशावाद नहीं है, बल्कि आंकड़ों का आधार देश की औसत प्रजनन दर में गिरावट है। किसी ने कितने बच्चों को जन्म दिया है, इसकी कुल प्रजनन दर (ळम्ट्रफ) 'कुल प्रजनन दर' के कारक से निर्धारित की जा सकती है। अर्थात, प्रति महिला बच्चों की संख्या प्रति व्यक्ति जन्म देती है। इतने लंबे समय तक यह 2।1 थी। अब यह घटकर 1।9 प्रतिशत हो गई है। स्थानांतरण दर 'से कम है। जनसंख्या के स्थिर रहने के लिए 'प्रतिस्थापन दर' एक आवश्यक कारक है। यह स्थानांतरण दर दशाती है कि जितने अधिक लोग मरते हैं, उतने ही नए जीव पैदा होते हैं। 'जितने गए, उतने ही आए' के अनुपात को बनाए रखने के लिए। हमारी प्रजनन दर को पहली बार 1।9 प्रतिशत तक नीचे आना होगा। तो यह 'जो चला गया है उससे कम' होगा और अगर यह जारी रहा, तो कुछ समय बाद जनसंख्या कम हो जाएगी।



नेतन्याहू का विवादास्पद बयान-ईरान के सर्वोच्च नेता की हत्या से ‘संघर्ष खत्म होगा, बढ़ेगा नहीं’

एजेंसी
जेरूसलम। इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बड़ा और विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने इशारा किया है कि ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई को निशाना बनाना एक संभावित विकल्प हो सकता है और यह संघर्ष को बढ़ाने की बजाय खत्म कर देगा। यह टिप्पणी उन्होंने एक अमेरिकी न्यूज चैनल से बात करते हुए की। जब उनसे सीधा सवाल पूछा गया कि क्या खामेनेई की हत्या एक विचाराधीन विकल्प है, तो नेतन्याहू ने कहा, हम वो कर रहे हैं जो हमें करना है।- उन्होंने आगे कहा कि यह शासन पिछले पचास वर्षों से पूरे मध्य पूर्व को आतंकित करता आया है। ईरान एक हमेशा का युद्ध चाहता है, और हमें परमाणु युद्ध की कगार पर ला रहा है। इजराइल जो कर रहा है, वह इस आक्रामकता को रोकने और इसे खत्म करने की दिशा में है। नेतन्याहू ने कहा कि अगर ईरान के सर्वोच्च नेता हत्या से संघर्ष समाप्त होता है तो यह बेहतर विकल्प है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि शायद यह एकमात्र तरीका है। बुराई की ताकतों के खिलाफ डटकर खड़ा होना ही होगा।

कैलगरी में प्रधानमंत्री मोदी का फोकस रहेगा वैश्विक प्राथमिकताओं पर

कैलगरी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां पहुंचने पर कहा कि उनका फोकस वैश्विक प्राथमिकताओं पर रहेगा। उन्होंने कुछ समय पहले एक्स पर लिखा, जी-7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कैलगरी (कनाडा) पहुंच गया हूं। शिखर सम्मेलन में विभिन्न नेताओं से मुलाकात करूंगा और महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर अपने विचार साझा करूंगा। वैश्विक दक्षिण की प्राथमिकताओं पर भी जोर दूंगा। कैलगरी कनाडा के अल्बर्टा प्रांत का एक प्रमुख शहर है। कैलगरी प्रांत के दक्षिणी भाग के कनाडाई रॉकीज के पूर्व में ऊंचे मैदानों और तलहटी के क्षेत्र में स्थित है। जी- 7 शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी की लगातार छठी भागीदारी है। यह यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की तीन देशों की आधिकारिक यात्रा का हिस्सा है। इसकी शुरुआत साइप्रस से हुई और इसका समापन क्रोएशिया में होगा। कैलगरी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अन्य प्रमुख राष्ट्रपति मौजूद हैं।

इजराइल-ईरान संघर्ष के चौथे दिन जान-माल का भारी नुकसान, कूटनीतिक प्रयास टप

तेहरान/जेरूसलम। इजराइल और ईरान के बीच चल रहा घातक सैन्य टकराव चौथे दिन और उग्र रहा। दोनों देशों के बीच मिसाइल और ड्रोन हमलों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा, जिससे जनहानि के साथ-साथ कूटनीतिक संवाद भी टप पड़ गया है।

ईरान ने इजराइल पर दार्जी 370 मिसाइलें
इजराइली प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, अब तक ईरान ने 370 बैलिस्टिक मिसाइलें और सैकड़ों ड्रोन इजराइल की ओर दागे हैं, जिनमें 30 ठिकानों को नुकसान पहुंचा है। जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने तेहरान, केरमांशाह समेत कई ईरानी शहरों पर हमले किए, जिनमें एक मिसाइल निर्माण इकाई और एक अस्पताल भी क्षतिग्रस्त हुआ। इन हमलों में जहां इजराइल में 24 लोगों की मौत हुई और 592 लोग घायल हुए। घायलों में 10 की हालत नाजुक है। वहीं, ईरानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक के इजराइली हमले में 224 नागरिक मारे गए हैं।

आरोप-प्रत्यारोप और जवाबी कार्रवाई की चेतावनी
इजराइली रक्षा मंत्री इसराइल काटज ने ईरानी नेतृत्व को कायर हथियार कापर देते हुए कहा कि तेहरान के नागरिकों को इसकी कीमत चुकानी होगी और वह समय दूर नहीं। वहीं, ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकन ने जवाब दिया कि इस युद्ध की शुरुआत हमने नहीं की, लेकिन हम हमले के स्तर के अनुसार प्रतिक्रिया जरूर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि जब तक इजराइल हमले नहीं रोकता, तब तक परमाणु वार्ता में भाग नहीं लिया जाएगा।

इजराइल ने ईरान के नए आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ अली शादमानी को मार गिराया

तेहरान (ईरान)। ईरान और इजराइल के बीच छिड़े भीषण सैन्य टकराव का आज पांचवां दिन है। तेज हुए हवाई हमलों से दोनों देशों के आसमान से धरती पर ‘मौत’ बरस रही है। ड्रोन, मिसाइल और बमबारी के धमाकों से कानों के परदे सुन्न पड़ने लगे हैं। यह लड़ाई ईरान को काफी भारी पड़ रही है। ईरान की सेना के दर्जनभर टॉप कमांडर मारे जा चुके हैं। कई परमाणु वैज्ञानिकों की जान का चुकी है। सैन्य ठिकानों को भी भारी नुकसान हुआ है। इजराइल के ताजा मिसाइल हमले में ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई के करीबी शीर्ष सैन्य अधिकारी अली शादमानी जान चली गई। हालांकि, ईरान ने शादमानी की मौत के बारे में इजराइल के दावों पर अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। अमेरिका के सीएनएन चैनल ने अपनी खबर में इजराइली वायुसेना के हवाले से कहा कि ताजा हमले में खामेनेई का करीबी और इस्लामिक रिजोल्यूशनरी गार्ड कॉर्पस (आईआरजीसी) के खतम-अल आँबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के प्रमुख अली शादमानी की मौत हो गई है। इजराइली रक्षा बलों ने सटीक खुफिया जानकारी के आधार पर पूरी रात ईरान में हमला किया है। इजराइली वायुसेना ने तेहरान के केंद्र में एक स्टाफयुक्त कमांड सेंटर पर हमला कर अली शादमानी को मार गिराया।

ईरान-इजरायल संघर्ष : दूतावास ने भारतीय छात्रों को तेहरान से निकाला

एजेंसी
तेहरान । ईरान-इजरायल के बीच बढ़ते तनाव के मद्देनजर भारतीय दूतावास, तेहरान में मौजूद भारतीय छात्रों को शहर से बाहर निकाल चुका है। इसके साथ ही अन्य लोग, जिनके पास खबर का ट्रंस्पोजेंट है, उन्हें भी शहर से बाहर जाने की सलाह दी गई है। इसके साथ ही कुछ भारतीयों को आर्मेनिया की सीमा के माध्यम से ईरान छोड़ने में मदद की गई है। दूतावास हरसंभव सहभाग्य प्रदान करने के उद्देश्य से अपने लोगों के साथ लगातार संपर्क में बना हुआ है।भारत ने ईरान में अपने नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों (पीआईओ) से इलाके में बढ़ते तनाव के मद्देनजर तेहरान खाली

प्रधानमंत्री की साइप्रस यात्रा से रणनीतिक सहयोग को बढ़ावा, ‘एक्शन प्लान’ तैयार करने पर सहमति बनी

एजेंसी
नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऐतिहासिक साइप्रस यात्रा ने भारत की वैश्विक कूटनीति को नई दिशा दी है। अपनी दो दिवसीय यात्रा (15-16 जून) के दौरान प्रधानमंत्री ने साइप्रस की एकता, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया।द्विपक्षीय संबंधों की दिशा तय करने के लिए 2025 से 2029 तक की एक विस्तृत ‘एक्शन प्लान’ तैयार करने पर सहमति बनी। दोनों देशों के विदेश मंत्रालय इस कार्य योजना के



है। ईरान में भारतीय दूतावास ने एक्स पर पोस्ट किया, सभी भारतीय नागरिक और पीआईओ, जो अपने संसाधनों का उपयोग करके तेहरान से बाहर निकल सकते हैं, उन्हें शहर के बाहर सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह दी जाती है। सभी भारतीय

कार्यान्वयन की निगरानी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स के साथ आतंक और आतंकवाद के प्रति राष्ट्रपति भवन पहुंचने पर उनका औपचारिक स्वागत किया गया। एक दिन पहले राष्ट्रपति स्वयं एयरपोर्ट पर स्वागत के लिए पहुंचे थे। यह दोनों देशों की गहरी मित्रता को दर्शाता है।दोनों नेताओं ने साझा मूल्यों, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति प्रतिबद्धता दोहराई। प्रधानमंत्री ने अप्रैल 2025 के पहलुगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा और भारत के

साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने पीएम मोदी को दिखाया निकोसिया शहर

एजेंसी
साइप्रस। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस दौरे से जुड़ी कुछ तस्वीरों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा किया। उन्होंने साइप्रस के निकोसिया शहर को दिखाने के लिए राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स का आभार जताया। उन्होंने कहा कि हमें साइप्रस के साथ लोगों के बीच और घनिष्ठ संबंधों की आशा है। पीएम मोदी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स की धन्यवाद कि उन्होंने मुझे निकोसिया के ऐतिहासिक शहर के कुछ हिस्सों को दिखाया। हमें साइप्रस के साथ लोगों के बीच और घनिष्ठ संबंधों की आशा है। इससे पहले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साइप्रस ने अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III’ से सम्मानित किया है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस

क्रिस्टोडोलाइड्स ने उन्हें यह सम्मान दिया। पीएम मोदी ने साइप्रस का सर्वोच्च सम्मान मिलने पर सोशल



मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘साइप्रस के ‘ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III’ का

मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स ने संयुक्त रूप से मीडिया को संबोधित किया।

फ्रांस ने पेरिस एयरशो में हथियार स्टॉल बंद करने का इजराइल ने जताया विरोध

एजेंसी
पेरिस। फ्रांस और इजराइल के बीच पारंपरिक मित्रता के बावजूद गाजा को लेकर बढ़ती कूटनीतिक संवेदनशीलता के चलते फ्रांस ने पेरिस एयरशो में इजराइल की प्रमुख रक्षा कंपनियों के स्टॉल बंद कर दिए।

फ्रांसीसी सरकार का कहना है कि इन कंपनियों को हमलावर हथियार प्रदर्शित करने से पहले ही रोक की चेतावनी दी गई थी, जिसे नजरअंदाज किया गया। प्रधानमंत्री फ्रांस्वा बैरू के कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि एयरशो में भाग लेने वाले सभी प्रदर्शकों को पहले ही सूचित कर दिया गया था कि आक्रामक हथियारों को प्रदर्शित करने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही, इजराइल दूतावास ने इस प्रतिबंध को मानने पर सहमति भी जताई थी। प्रवक्ता ने यह भी स्पष्ट किया कि

यदि इजराइली कंपनियां नियमों का पालन करती हैं, तो उन्हें अपने स्टॉल फिर से खोलने की अनुमति



दी जा सकती है। फ्रांस्वा बैरू ने पत्रकारों से बातचीत में कहा, फ्रांस की कूटनीतिक नीति और विशेष रूप से गाजा को लेकर गहरी चिंता के मद्देनजर ऐसे आक्रामक हथियारों की

आलोचना की है और इसे फ्रांस-इजराइल संबंधों में एक असहज मोड़ बताया है। एयरशो में प्रतिबंध से यह स्पष्ट है कि गाजा संकट पर वैश्विक दृष्टिकोण अब रक्षा उद्योग को भी प्रभावित कर रहा है।

‘बिना पैसे और साधनों के हमला नहीं हो सकता’, एफएटीएफ ने पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की

एजेंसी
पेरिस। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ने 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले की कड़ी निंदा की। एफएटीएफ ने कहा कि यह हमला आतंकी समर्थकों के बीच धन और फंड ट्रांसफर के साधनों के बिना संभव नहीं हो सकता था। एफएटीएफ ने एक बयान में कहा कि आतंकी हमले दुनिया भर में लोगों की जान लेते हैं, उन्हें अपंग बनाते हैं और भय पैदा करते हैं। पहलगाम में 22 अप्रैल 2025 को हुए क्रूर आतंकवादी हमले पर एफएटीएफ गंभीर चिंता व्यक्त करता है और इसकी निंदा करता है। इस तरह के हमले बिना धन और आतंकी समर्थकों के बीच फंड ट्रांसफर के साधनों के संभव नहीं हो सकते। बयान में आगे कहा गया, ‘जैसा कि एफएटीएफ अध्यक्ष ने न्यूजकॉ में हाल ही में आयोजित ‘नो मीन फॉर टेरर’ सम्मेलन में बताया, कोई अकेली कंपनी, प्राधिकरण या देश इस चुनौती का सामना अकेले नहीं कर सकता। हमें वैश्विक आतंकवाद के खतरे

के खिलाफ एकजुट होना होगा क्योंकि आतंकवादियों को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए केवल एक बार सफल होने की जरूरत होती है, जबकि हमें इसे रोकने के लिए हर बार सफल



होना पड़ता है।’ जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले में 26 निदोष पर्यटक मारे गए थे। पहलगाम आतंकी हमले की जांच में आतंकियों के पाकिस्तान से संचार

नेटवर्क का पता चला। द रिसिस्टेंस फ्रंट (टीआरएफ) नामक समूह ने, जो संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंधित पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुख्या है, इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। हालांकि, बाद में उसने वह पलट गया था। भारत ने मई और नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र की 1267 प्रतिबंध समिति की निगरानी टीम को अर्ध-वार्षिक रिपोर्ट में टीआरएफ के बारे में जानकारी दी थी, जिसमें पाकिस्तान स्थित आतंकवादी समूहों के लिए एक आवरण के रूप में इसकी भूमिका को सामने लाया गया था। इससे पहले, दिसंबर 2023 में भारत ने लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के बारे में जानकारी दी थी, जो टीआरएफ जैसे छोटे आतंकी समूहों के माध्यम से काम कर रहे हैं। ‘ऑपरेशन सिंदूर’ के दौरान विदेश मंत्रालय (एम्ईए) ने 25 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रेस वक्तव्य में टीआरएफ के संदर्भों को हटाने के लिए पाकिस्तान के दबाव को उजागर किया था।

जी7 ने इजरायल का समर्थन किया, ईरान को बताया ‘क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का स्रोत’

एजेंसी
टोरंटो । इजरायल-ईरान में पिछले पांच दिनों से संघर्ष जारी है। इस तनाव के बीच मंगलवार को ग्रुप ऑफ सेवन (जी7) देशों के नेताओं ने मिडिल-ईस्ट में शांति और स्थिरता के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है। इसके साथ ही इजरायल के आत्मरक्षा के अधिकार को सपोर्ट किया है। शिखर सम्मेलन से जारी एक संयुक्त बयान में, जी7 नेताओं ने ईरान को क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का मुख्य स्रोत बताया है। उन्होंने ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सभी पक्षों से गाजा में युद्ध विराम और तनाव कम करने की दिशा में आगे बढ़ने का आग्रह किया है। बयान

में कहा गया, हम जी-7 के नेता, मिडिल-ईस्ट में शांति और स्थिरता के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। इस संदर्भ में, हम पुष्टि करते हैं कि इजरायल को अपनी रक्षा करने का अधिकार है। हम इजरायल की सुरक्षा के लिए अपना समर्थन दोहराते हैं। हम नागरिकों की सुरक्षा के महत्व की भी पुष्टि करते हैं। ईरान क्षेत्रीय अस्थिरता और आतंक का मुख्य स्रोत है। हमारा स्पष्ट मत है कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। इसके साथ हम ये भी आह्वान करते हैं कि ईरानी संकट का समाधान हो जिससे मिडिल ईस्ट में तनाव कम हो। हम गाजा में भी युद्धविराम चाहते हैं। बयान में बढ़ते तनाव के बीच पुनर्जी माफ़ेकट की स्थिरता को बनाए रखने के लिए जी7 की कार्रवाई करने

की तत्परता को भी रेखांकित किया गया है। इस बीच, तनाव और बढ़ गया है। इजरायल ने तेहरान के निवासियों को हवाई हमलों से पहले शहर खाली करने की चेतावनी दी है। इजरायली अधिकारियों ने नागरिकों से तत्काल ईरानी राजधानी छेड़ने की अपील की है, जो एक बड़े पैमाने पर हमले का संकेत है। गिरावटी स्थिति के जवाब में, संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जी7 शिखर सम्मेलन के लिए अपनी यात्रा को एक दिन कम कर दिया। इजरायल-ईरान के इस तनाव के बीच दोनों देशों ने एक-दूसरे के खिलाफ मिसाइल और ड्रोन का इस्तेमाल किया है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर ट्रंप ने लोगों से तेहरान को खाली करने को कहा है।

राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द करने का प्रयास किया गया है। इजरायल ने आतंकवाद के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पनाहनाह और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के समर्थन की दिशा में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने संयुक्त

राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द करने का प्रयास किया गया है। इजरायल ने आतंकवाद के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पनाहनाह और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के समर्थन की दिशा में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने संयुक्त

राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द करने का प्रयास किया गया है। इजरायल ने आतंकवाद के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पनाहनाह और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के समर्थन की दिशा में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने संयुक्त

राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द करने का प्रयास किया गया है। इजरायल ने आतंकवाद के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पनाहनाह और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के समर्थन की दिशा में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने संयुक्त

राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द करने का प्रयास किया गया है। इजरायल ने आतंकवाद के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पनाहनाह और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के समर्थन की दिशा में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने संयुक्त

राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द करने का प्रयास किया गया है। इजरायल ने आतंकवाद के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पनाहनाह और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के समर्थन की दिशा में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने संयुक्त

राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द करने का प्रयास किया गया है। इजरायल ने आतंकवाद के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पनाहनाह और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के समर्थन की दिशा में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने संयुक्त

राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द करने का प्रयास किया गया है। इजरायल ने आतंकवाद के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पनाहनाह और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के समर्थन की दिशा में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने संयुक्त

राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द करने का प्रयास किया गया है। इजरायल ने आतंकवाद के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पनाहनाह और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के समर्थन की दिशा में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने संयुक्त

राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द करने का प्रयास किया गया है। इजरायल ने आतंकवाद के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पनाहनाह और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के समर्थन की दिशा में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने संयुक्त

राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द करने का प्रयास किया गया है। इजरायल ने आतंकवाद के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पनाहनाह और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के समर्थन की दिशा में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने संयुक्त

राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द करने का प्रयास किया गया है। इजरायल ने आतंकवाद के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पनाहनाह और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के समर्थन की दिशा में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने संयुक्त

राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द करने का प्रयास किया गया है। इजरायल ने आतंकवाद के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पनाहनाह और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के समर्थन की दिशा में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने संयुक्त

राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द करने का प्रयास किया गया है। इजरायल ने आतंकवाद के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पनाहनाह और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के समर्थन की दिशा में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने संयुक्त

राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द करने का प्रयास किया गया है। इजरायल ने आतंकवाद के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पनाहनाह और बुनियादी ढांचे को समाप्त करने के समर्थन की दिशा में प्रगति की आवश्यकता बताई। उन्होंने संयुक्त

राष्ट्र और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) के अंतर्गत आतंकवाद से संबंधित प्रस्तावों के प्रभाव को आंशिक रूप से रद्द करने का प्रयास किया गया है। इजरायल ने आतंकवाद के समापन का समर्थन किया। समुद्री, हरित ऊर्जा, रक्षा और अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग की दिशा में प्रगति की सराहना की गई।

कंपनियों को साइप्रस में उपस्थिति बढ़ाने और संयुक्त समुद्री परियोजनाओं के जरिये समुद्री सहयोग को मजबूत करने की सहमति बनी। दोनों नेताओं ने वैश्विक शासन प्रणाली में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। साइप्रस ने सुरक्षा परिषद के विस्तार में भारत को स्थायी सदस्य बनाने के लिए अपना समर्थन दोहराया। दोनों देशों ने आतंकवाद के वित्तपोषण, पना

जुदा हुए कुशल टंडन और

शिवांगी जोशी

एक्टर ने दी ब्रेकअप की जानकारी,
बोले- कोई पछतावा नहीं

शिवांगी जोशी और कुशल टंडन के फैसले के लिए एक बुरी खबर है। दरअसल टीवी के मशहूर एक्टर कुशल टंडन, 'ये रिश्ता क्या कहलाता है' फेम खूबसूरत शिवांगी जोशी कुछ समय से डेट कर रहे थे, ये भी कहा जा रहा था कि दोनों जल्द ही शादी कर सकते हैं। लेकिन अब कुशल टंडन ने खुद सोशल मीडिया पर शिवांगी के साथ अपने ब्रेकअप की जानकारी दी, हालांकि सोशल मीडिया पर ब्रेक अप की पुष्टि करने के कुछ समय बाद ही कुशल ने अपनी ये इंस्टाग्राम स्टोरी डिलीट कर दी। कुशल टंडन ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी में साफ-साफ लिखा था, मुझसे प्यार करने वाले मेरे सभी फैसले को मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं और शिवांगी अब एक साथ नहीं हैं। इस बात को अब 5 महीने हो गए हैं। यानी कुशल ने सीधे तौर पर बता दिया है कि वो और शिवांगी अब अलग हो चुके हैं। इस स्टोरी के तुरंत बाद, उन्होंने अगली स्टोरी में लिखा, मैं सिंगल और खुश हूँ और इस बात का मुझे कोई पछतावा नहीं है। हालांकि, इन दोनों स्टोरीज को कुशल ने कुछ ही समय बाद हटा दिया, लेकिन ये खबर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है।

सीरियल के सेट पर हुआ था प्यार

कुशल टंडन और शिवांगी जोशी की मुलाकात टीवी सीरियल 'बरसातों में मौसम प्यार का' के सेट पर हुई थी। इस शो में दोनों ने लीड रोल निभाया था और उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। सीरियल के दौरान ही दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई थी, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। भले ही दोनों ने एक दूसरे के साथ रिश्ते को लेकर कोई पुष्टि नहीं की थी। लेकिन दोनों ने इस बात से इनकार भी नहीं किया था। शिवांगी जोशी और कुशल टंडन को उनका सीरियल खत्म होने के बाद भी कई बार एक साथ देखा गया था और उनके सोशल मीडिया पोस्ट भी उनके रिश्ते की तरफ इशारा कर रहे थे।

फैंस हुए हैरान

कुशल के इस अचानक खुलासे से फैंस हैरान रह गए, क्योंकि कई लोगों को लग रहा था कि इन दोनों का रिश्ता काफी मजबूत है। हालांकि, कुशल ने ब्रेकअप की कोई खास वजह नहीं बताई है। बस इतना कहा कि वे पांच महीने से अलग हैं और वो अकेले खुश हैं। फिलहाल, शिवांगी जोशी की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है।

इरफान खान

कोंकणा सेन

की जोड़ी, केके का अलविदा... 18 साल बाद कितनी बदल गई मेट्रो लाइफ?

अनुराग बासु की आने वाली फिल्म मेट्रो इन दिनों के ट्रेलर ने आज से अठारह साल पीछे जाने पर मजबूर कर दिया। यह फिल्म चार जुलाई को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। इस फिल्म की कहानी में एक बार फिर से महानगरों की जिंदगी दिखाने की कोशिश की जाएगी, जैसा कि फिल्म का ट्रेलर देखने से जाहिर होता है। यह फिल्म इसलिए खासी मायने रखती है क्योंकि अनुराग बासु ने जब साल 2007 में लाइफ इन मेट्रो बनाई थी, तब उस फिल्म ने महानगरीय जिंदगी जीने वालों को एक प्रकार से झकझोर दिया था। फिल्म दिल्ली और मुंबई जैसे शहरों में रहने वाले मध्यवर्गीय सोसायटी का आईना कहलाई। उस फिल्म की यादें आज भी ताजा हैं। इरफान-कोंकणा और शाइनी- शिल्पा की केमिस्ट्री भूलना मुश्किल है। मेट्रो इन दिनों का ट्रेलर देखने के बाद उसकी एक झलक आंखों में फिर से बाँध गई।

वहीं अलविदा गाने के साथ केके की आवाज भी कारों में फिर से गुंज गई। अनुराग बासु की मेट्रो इन दिनों में कुछ कलाकार लाइफ इन मेट्रो के हैं तो कुछ अलग भी। मसलन आदित्य रॉय कपूर, सारा अली खान, अली फजूल, फातिमा सना शेख, कोंकणा सेन शर्मा, पंकज त्रिपाठी, नीना गुप्ता, अनुपम खेर और शास्वत चटर्जी आदि। मेट्रो इन दिनों को अठारह साल पुरानी चर्चा और प्रतिष्ठा दिलाने का भार इन्हीं कलाकारों के कंधे पर है। इन नामों की सूची देखने के बाद जाहिर होता है कि डायरेक्टर ने इसमें कोंकणा सेन शर्मा को फिर से याद किया है और बाकी कलाकार सब बदल दिए हैं।

इरफान और कंगना के बिना मेट्रो इन दिनों

साल 2007 में आई लाइफ इन मेट्रो में शिल्पा शेठ्टी, के के मेनन, शाइनी आहूजा,

नफीसा अली, कंगना रनौत, शरमन जोशी के अलावा जिस कलाकार की उपस्थिति ने फिल्म को अलग रुतवा प्रदान किया, वह थे- इरफान खान और कंगना रनौत। इनके अलावा के के मेनन, शाइनी आहूजा भी फिल्म के खास आकर्षण थे। लेकिन 2025 की मेट्रो इन दिनों के दौर में इनकी परछाईयां ही शेष हैं। कंगना रनौत सांसद बन चुकी हैं और इस किस्म के रोल अब उन्हें रास नहीं आ रहे। वहीं इरफान खान फानी दुनिया से रुखसत कर चुके हैं।

मेट्रो इन दिनों को इरफान खान के बिना देखना बहुत ही कचोट पहुंचाने वाली संवेदना जगा सकता है। इरफान ने उस फिल्म में मोटी यानी श्रुति के प्रेमी का रोल निभाकर युवतियां हों या शादीशुदा महिलाएं- दोनों के बीच अलग किस्म की लोकप्रियता बटोरी थी। यह लोकप्रियता शाहरुख, सलमान वाली लोकप्रियता से अलग किस्म की थी। इरफान को इस फिल्म ने थ्रिंकिंग वुमेनज सिंबल की संज्ञा दी थी। वह केवल जुबान से संवाद नहीं बोलते थे बल्कि अपनी गोल आंखों के जरिए भी बखूबी बोलते थे।

कोंकणा सेन शर्मा के साथ इरफान की जोड़ी खूब जमी

उस फिल्म में श्रुति घोष के किरदार में कोंकणा सेन शर्मा के साथ उनकी जोड़ी बहुत ही अનોखी मानी गई थी। कोंकणा भी अपने ग्लैमर से कहीं ज्यादा अपने गंभीर अभिनय के लिए जानी जाती हैं। अनुराग बासु की लाइफ इन मेट्रो से कोंकणा सेन शर्मा की पहचान को नया फॉर्मेट मिला था। इरफान और कोंकणा बतौर प्रेमी-प्रेमिका उस फिल्म की एक साख बनें। कमर्शियल होकर भी फिल्म को एक अलग फॉर्मेट मिला, जिसे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी वर्ग ने भी पसंद किया।

अहमदाबाद हादसे के बाद एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठी रवीना टंडन, अंदर का नजारा देखकर हिल गई



अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश से देश अब तक उबर नहीं पाया है। अहमदाबाद से यात्रियों को लंदन ले जा रहा विमान उड़ने के एक मिनट के अंदर ही क्रैश हो गया था। इसमें महज एक यात्री जीवित बच पाया। बाकी सभी 241 लोगों की मौत हो गई। इनमें यात्रियों के साथ ही कर्नल भी शामिल हैं। वहीं जिस जगह प्लेन गिरा था वहां के भी कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। इस हादसे के बाद लोग प्लेन के नाम से डरने लगे हैं और हवाई जहाज में सफर करने से दूरी बनाने लगे हैं।

इस भीषण हादसे पर देश दुनिया के लोगों और दिग्गज हस्तियों ने भी शोक व्यक्त किया था। बॉलीवुड ने भी पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की थी। अब हादसे के कुछ दिनों बाद ही रवीना टंडन ने एयर इंडिया की फ्लाइट से उड़ान भरी है। मालूम हो कि हादसे का शिकार हुआ विमान भी एयर इंडिया का ही था। रवीना जब सफर के लिए प्लेन के अंदर गई तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने जो नजारा देखा वो सारी कहानी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बयां की है।

रवीना ने प्लेन के अंदर से शेयर की फोटोज

रवीना टंडन ने 16 जून, सोमवार को अपने इंस्टाग्राम हैंडल से अपनी कई तस्वीरें शेयर की हैं। वो एयर इंडिया विमान के भीतर बैठी हुई नजर आ रही हैं। एक्स्ट्रेस ने इन तस्वीरों में अपना टिकट भी शेयर किया है। साथ ही बताया कि आखिर अहमदाबाद हादसे के कुछ दिनों के बाद अब एयर इंडिया की फ्लाइट में कैसा माहौल है? रवीना ने कैप्शन में लिखा, नई शुरुआत सभी बाधाओं के बावजूद फिर से उड़ान भरना और मजबूत होना। सवारियों का सन्नाटा और कर्नल की मुस्कान में दुख छिपा हुआ था। यात्रियों और कर्नल के बीच चुपके से संवेदनाएं दिख रही हैं।

रवीना ने आगे अपनी बात जारी रखते हुए लिखा, उन परिवारों के प्रति संवेदनाएं, जिन्होंने अपने प्रियजनों को खो दिया है। एक ऐसा घाव जो कभी नहीं भरगा। भगवान हमेशा आपकी मदद करें एयर इंडिया। निडर होकर फिर से मजबूत बनने की इच्छा। जय हिंद।

12 जून को हुआ था हादसा

कर्नल मेजर और यात्रियों सहित 242 लोगों को 12 जून की दोपहर को अहमदाबाद से लंदन ले जा रहा विमान उड़ान भरने के ठीक बाद अहमदाबाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। हादसे का शिकार हुए लोगों के शवों की शिनाख्त फिलहाल DNA सेंपल के जरिए की जा रही है।

करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय की आखिरी तस्वीर आई सामने!



बॉलीवुड एक्ट्रेस करिश्मा कपूर ने 2016 में अपने पति संजय कपूर को तलाक दे दिया था। लेकिन बच्चों के कारण दोनों की मुलाकातें होती रहती थीं, जो करिश्मा के पास रहते हैं। 12 जून की रात जब खबर आई कि करिश्मा कपूर के एक्स हसबैंड संजय कपूर की डेथ हो गई है तो इस खबर ने हर किसी को हैरानी में डाल दिया। संजय कपूर का निधन पोलो खेलते समय हुआ और पोलो क्लब की तरफ से संजय कपूर की आखिरी तस्वीर एक दिन पहले शेयर की गई है। इस तस्वीर में संजय कपूर हंसते हुए नजर आए।

दिल्ली के रहने वाले बिजनेसमैन संजय कपूर ज्यादातर यूके में ही रहते थे। यहां उन्होंने गार्ड्स पोलो क्लब में Sujan Indian Tigers Polo Team ज्वाइन की हुई थी और पूरी टीम के साथ उनकी अच्छी दोस्ती थी। उनके साथ ही संजय अक्सर पोलो खेलने जाते थे। इस क्लब के इंस्टाग्राम पेज पर ही संजय कपूर की आखिरी मुस्कुराती तस्वीर शेयर की गई है और साथ में एक लंबा पोस्ट भी लिखा गया है। इस तस्वीर में सुजान इंडियन टाइगर्स के ओनर भी नजर आ रहे हैं।

संजय कपूर की आखिरी तस्वीर हुई वायरल

तस्वीर शेयर करने के साथ ही इसके कैप्शन में लिखा गया, 'आज हम अपने डियर फ्रेंड संजय कपूर की याद में कार्टियर ट्रॉफी का फाइनल खेलेंगे, जिनकी कुछ दिन पहले मैदान पर ट्रैजिकली डेथ हो गई थी। हमारे कैप्टन और संरक्षक, जैसल सिंह अपने पुराने दोस्त संजय कपूर के सम्मान में एक मिनट का मौन रखने के लिए टीम के साथ जाएंगे और फिर सम्मान के प्रतीक के रूप में बाहर बैठेंगे। संजय और जैसल की यह तस्वीर कुछ दिन पहले सेमीफाइनल खेलने के लिए तैयार होने से कुछ समय पहले ही ली गई थी। RIP संजय, आपकी याद आएगी, आपने इस क्लब में जो योगदान दिया वो हमेशा याद रखा जाएगा।'

करिश्मा कपूर और संजय कपूर कब हुए अलग ?

2003 में करिश्मा कपूर ने दिल्ली के रहने वाले बिजनेसमैन संजय कपूर से शादी की थी। उनके दो बच्चे समायरा और कियान हैं जो पैरेंट्स के तलाक के बाद करिश्मा के पास ही रहते हैं।

संजय कपूर ने तलाक के बाद प्रिया सचदेव से शादी कर ली थी, जिनसे उन्हें एक बेटी भी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, करिश्मा कपूर से पहले संजय कपूर ने 1996 में नंदिता महतानी के साथ शादी की थी, जिनसे वो 2000 में अलग हो गए थे।

पत्रकारों की आवाज बनकर गरजी श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की प्रदेशाध्यक्ष डॉ इन्दु बंसल

दिव्य दिल्ली: गोहाना चंडीगढ़,वीरवार,19 जून 2025 श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की गोहाना इकाई द्वारा श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की पत्रकार हितैषी नीतियों व सरकार से पत्रकार हितों की लंबित मांगों को लेकर गोहाना में प्रेस वार्ता का आयोजन व श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की गोहाना जिला इकाई की बैठक का आयोजन किया गया।इस प्रेस वार्ता को श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की संस्थापक व प्रदेशाध्यक्ष डॉ इन्दु बंसल ने संबोधित करते हुए कहा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा ने 6 माह की अल्पावधि में हरियाणा में पत्रकार हितों को लेकर एक अलग मिसाल कायम की है प्रेस वार्ता में उन्होंने ने कहा की 6 जिलों में श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की जिला कार्यकारिणी गठित हो चुकी हैं जल्द ही आगामी एक माह के अंदर 8 जिलों व राजधानी चंडीगढ़ में श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की कार्यकारिणीयां गठित कर दी जाएंगी। डॉ बंसल ने सरकार से पत्रकारों की लंबित मांगों को जल्द से जल्द



पूरा करने की बात कहते हुए कहा कि श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा ने समय समय पर कार्यक्रमों का आयोजन कर अपने मंचों पर सरकार के नुमाइंदों को बुला कर पत्रकारों की समस्याओं से अवगत करवा उन्हें मांग पत्र देता रहता है। उन्होंने पूरा विश्वास है कि सरकार पत्रकारों की लंबित मांगों को जल्द पूरा करेगी।इस संदर्भ में श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा आगामी 22 जून को पटौदी व 29 जून को रेवाड़ी में प्रदेशस्तरीय पत्रकार सम्मान समारोह का आयोजन कर पत्रकारों का सम्मान तो करेगा ही साथ ही सरकार के नुमाइंदों को

एक बार फिर से अपने मंच पर आमंत्रित कर पत्रकारों की समस्याओं से अवगत भी करवाएगा।डॉ बंसल ने कहा की आगामी अगस्त तक श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की 14 जिलों में जिला कार्यकारिणी गठित हो जाएंगी तब 14 जिलों के पत्रकारों का एक प्रदेश स्तरीय पत्रकार सम्मेलन आयोजित होगा जिस में एक बार फिर से सरकार को पत्रकारों की लंबित मांगों को लेकर फिर से चेताया जयेगा।संघ के विस्तार पर बोलते हुए डॉ बंसल ने कहा हमारा लक्ष्य है श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा के स्थापना दिवस 16 नवम्बर (प्रेस दिवस) तक हरियाणा में

संघ की 27 जिलों में जिला कार्यकारिणी गठित हो चुकी होगी और स्थापना दिवस (16 नवम्बर) पर हरियाणा में श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा के तत्वाधान में अद्वितीय पत्रकार सम्मेलन का आयोजन होगा जिस सम्मेलन में प्रदेश भर से हजारों पत्रकार सम्मेलन में आएंगे व सरकार के समक्ष अपनी लंबित मांगों को पुरजोर तरीके से रखेंगे। *श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की सरकार से मांगे हरियाणा में महाराष्ट्र व छत्तीसगढ़ की तर्ज पर पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हो।एक्रीडिटेसन के नियमों में सरलीकरण हो। पत्रकार पेंसन का नाम बदल कर पत्रकार सम्मान निधि किया जाए साथ ही पेंसन की राशि 15 हजार से बढ़ा के 25 हजार की जाए व आयु सीमा 60 वर्ष से 55 वर्ष की जाए। ग्रुप हाउसिंग सोसायटी के तहत पत्रकारों को रियायती दरों पर रिहारशी मकान उपलब्ध किये जाए। दफ्तर के नियमों में सरलीकरण हो जिस से लघु समाचार पत्रों को सुविधा मिल सके।हरियाणा सरकार द्वारा निकट भविष्य में बनाये जा रहे 5

नए जिलों में भी मीडिया सेंटर बनाये जाए। पत्रकारों के वाहनों को टोल मुक्त किया जाए।डॉ बंसल ने कहा की पत्रकारों की इन सभी अनिवार्य ,जायज व लंबित मांगों को लेकर श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा के वरिष्ठ पत्रकारों का एक दल बहुत जल्द हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी व राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय से भी मुलाकात करेगा।गोहाना में आयोजित इस प्रेस वार्ता में डॉ इन्दु बंसल के साथ प्रदेश संरक्षक डॉ डीएल मल्होत्रा, प्रदेश प्रवक्ता नवीन बंसल, गोहाना जिला अध्यक्ष अनिल जिंदल व श्रमजीवी पत्रकार संघ हरियाणा की गोहाना जिला इकाई के सभी पदाधिकारी व सदस्य उपस्थित थे। जिन में मुख्य रूप से वरिष्ठ पत्रकार सुनील जिंदल, भंवर सिंह, सारिका नरवाल,विवेक अहलावत, प्रीति सिंघल, अजय,तेजपाल शर्मा, मदन मोहन,परमजीत,संदीप, जोगिंदर सिंह,सौरभ,सुरेंद्र,नरेश शर्मा, रविंदर,मेनका, राजेश पांचाल, अजय सैनी,जगबीर जैन के साथ - साथ अनेकों पत्रकार उपस्थित थे।

वर्ल्ड फूड फेस्टिवल में शामिल होंगे दिल्ली के भी फूड कारोबारी - CTI

दिव्य दिल्ली : दिल्ली में 25 से 28 सितंबर को भारत मंडपम में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 के नाम से फेरिटवल आयोजित होने जा रहा है इसी सिलसिले में दिल्ली में व्यापारियों और फैक्ट्री मालिकों के शीर्ष संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री सीटीआई ने केन्द्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान से मुलाकात की,सीटीआई चेयरमैन बृजेश गोयल ने बताया कि दिल्ली में सितंबर में आयोजित होने वाले फूड फेस्टिवल में दिल्ली के फूड एवं खाद्य पदार्थों से जुड़े हुए व्यापारियों को भी शामिल किया जाए, बृजेश गोयल ने चिराग पासवान को बताया कि दिल्ली में विशेषकर पुरानी दिल्ली की चाट



पकोड़ी और खोमचे विश्व प्रसिद्ध हैं इसके अलावा दिल्ली में फूड सेक्टर में अलग अलग आइटम्स के बड़े बड़े ब्रांड हैं जिनको फूड फेस्टिवल में भग लेने का अवसर मिलना चाहिए, इस पर चिराग पासवान ने कहा कि फूड फेस्टिवल में सभी आमंत्रित हैं, ये वैश्विक कार्यक्रम है और दिल्ली की फूड इंडस्ट्री के व्यापारियों को भी इसमें हिस्सा लेना चाहिए, इसके लिए

अंतरराष्ट्रीय बाजार में रिकॉर्ड ऊंचाई पर चांदी

नई दिल्ली/एजेंसी सराफा बाजार के साथ ही वायदा बाजार में भी चांदी आज रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है। आज मूल्टी क्मोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सिल्वर प्यूचर 1.10 लाख रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर पहुंच गया। घरेलू बाजार की तरह ही अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी चांदी के भाव में लगातार तेजी का रुख बना हुआ है। आज कॉम्मेक्स पर चांदी 37.23 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया। पिछले 13 साल के दौरान चांदी पहली बार इस ऊंचाई पर पहुंचने में सफल रहा है। जारी रही, तो ये चमकीली धातु जल्दी ही 40 डॉलर प्रति औंस के स्तर को भी पार कर सकती है।

हिमाचल के लिए केंद्र से 2006 करोड़ रुपये की मंजूरी

नई दिल्ली/एजेंसी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केन्द्रीय मंत्री अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने हिमाचल प्रदेश में वर्ष-2023 में भीषण प्राकृतिक आपदाओं के चलते पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना के तहत 2006.40 करोड़ की राशि मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं गृह मंत्री अमित शर्मा के आभार जताया है। बुधवार को साझा किए अपने संदेश में जेपी नड्डा ने कहा कि देवभूमि में संकट से निपटने और आपदा पीड़ितों को राहत प्रदान करने में मोदी सरकार द्वारा आर्थिक सहायता आपदा पीड़ित

नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण सबल है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार देवभूमि की जनता के साथ हर संकट में खड़ी है और हिमाचल की हरसंभव सहायता के लिए सदैव की भांति कटिबद्ध है। उल्लेखनीय है कि बुधवार को केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने 2023 की बाढ़, भूस्खलन, बादल फटने की घटना के बाद हिमाचल प्रदेश के लिए 2006.40 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय के साथ पुनर्प्राप्ति और पुनर्निर्माण योजना को मंजूरी दी है।

दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी ने राष्ट्रीय राजधानी में जिद्दी जाट का ट्रेलर लॉन्च किया

दिव्य दिल्ली : रांझा विक्रम सिंह और सिंगा स्टारर फिल्म 'जिद्दी जट्ट' का हिंदी वर्जन का ट्रेलर दिल्ली के ले मेडियन होटल में लॉन्च किया गया। दिल्ली के सांसद मनोज तिवारी मुख्य अतिथि थे।इस फिल्म का निर्माण रनिंग हॉर्स फिल्म्स और ग्लोबल टाइम्स ने किया है और इसका निर्देशन सिमरनजीत सिंह ने किया है। इससे पहले वे 'जट्ट बांजट पुत जट्ट दे', '25 किल्ले, रब्बा रब्बा मिह वसा' जैसी कई लोकप्रिय फिल्मों का निर्देशन कर



चुके हैं।पंजाब में अवैध रेत खनन पर आधारित और एक्शन थ्रिलर फिल्म जिद्दी जट्ट में रांझा

विक्रम सिंह, सिंघा, सारा गुरपाल और बॉलीवुड अभिनेता प्रदीप रावत मुख्य भूमिका में हैं। फिल्म

दर्शकों को एक्शन, ड्रामा और माफिया संस्कृति का तड़का देती है। रांझा विक्रम सिंह बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता हैं और उन्होंने शाहरुख खान की फिल्म 'डंकी' में भी अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा अभिनेता रांझा विक्रम सिंह ने 'हीरोपंती', 'हीरोपंती' में मुख्य नकारात्मक भूमिका, '25 किल्ले या रब्बा', 'राणा विक्रमा', 'फोजी कॉलिंग' और कई अन्य सफल फिल्मों में भी काम किया है।

दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का सड़क सुरक्षा अभियान तेज

नई दिल्ली। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने राजधानी में सड़क सुरक्षा और ज़िम्मेदार ड्राइविंग व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक जागरूकता अभियान चलाया है। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (ट्रैफिक मुख्यालय) सत्य वीर कतारा के नेतृत्व में यह अभियान पूरे शहर में कई स्थानों पर सफलतापूर्वक आयोजित किया गया। महिलाओं की सुरक्षा, हेलमेट/सीट बेल्ट की अनिवार्यता, शराब पीकर गाड़ी न चलाने, गलत दिशा में न चलने जैसी सावधानियों के प्रति जागरूक किया गया।



राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिष्टाचार भेंट की।

संभल में सपा सांसद बर्क ने दंगा भड़काया विधायक के बेटे ने सीओ पर गोली चलवाई थी

संभल हिंसा: सपा सांसद समेत 23 के खिलाफ चार्जशीट

संभल/एजेंसी संभल हिंसा मामले में सपा सांसद जियाउर्रहमान बर्क की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बुधवार को पुलिस ने 1100 पन्नों की चार्जशीट चंदौसी टह/टछाउ कोर्ट में दाखिल की है। पुलिस ने सांसद बर्क और सपा विधायक इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल समेत 23 आरोपियों का हिंसा भड़काने का नामजद आरोपी बनाया है। पुलिस ने 700-800 अज्ञात को भी आरोपी बनाया है। 24 नवंबर, 2024 को जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान हिंसा भड़की थी। हिंसा में चार मुस्लिम युवकों की जान चली गई थी। एस्पी, सीओ और डिप्टी कलेक्टर समेत 29 पुलिसकर्मी घायल हुए थे। सांसद ने हिंसा भड़काई, विधायक के बेटे ने गोली चलवाई सांसद बर्क पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण देकर भीड़ को उकसाया। उन्होंने मस्जिद सदर जफर अली को 23 नवंबर की रात फोन करके कहा



था, 'कौम हम पर ही थुकेगी। सर्वे किसी भी सूरत में नहीं होना चाहिए। भीड़ इकट्ठा करो।' हिंसा के वक्त भीड़ में शामिल शहर विधायक नवाब इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल ने दंगाइयों को उकसाकर सीओ पर गोली चलवाई थी। इस मामले में पुलिस ने कोतवाली संभल में केस दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में जामा मस्जिद के सदर जफर अली

एडवोकेट सहित कुल 90 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। सांसद बर्क से एसआईटी ने 8 करीब चार घंटे पूछताछ की। इससे पहले 25 मार्च को रक्त के इम्पेक्टर अमरीश कुमार ने दिल्ली जाकर सांसद के आवास पर पूछताछ की नोटिस दिया था। दरोगा दीपक राठी ने सांसद जियाउर्रहमान बर्क और सुहेल इकबाल पर एफआईआर दर्ज कराई थी। कोर्ट के आदेश पर जामा

मस्जिद का पहला सर्वे 19 नवंबर, 2024 को हुआ था। इसके बाद 22 नवंबर को सांसद बर्क भीड़ के साथ जुमे की नमाज पढ़ने पहुंचे। तब उन्होंने कहा था- 'कसूरें गम से दो आंसू बहाएं तो आफत है, और सितम सारे जमाने के भूल जाएं तो बगावत है। समझ नहीं आता, छेड़ें तो दास्तां कैसे, हंसाए तो बगावत है, रुलाएं तो बगावत है। आज मैं जामा मस्जिद के अंदर गया, जो अल्लाह का घर है। आज से नहीं, कई साल से यह मस्जिद है। यहां इबादत करने के लिए सारे मुसलमान तशरीफ लाए हैं। ये कुछ नया नहीं है। हमेशा से यहां नमाज अदा की जा रही है। आज मैं भी नमाज के लिए हाजिर हुआ हूं। मुझे मालूम पड़ा कि पुलिस प्रशासन ने यहां बहुत तैयारी कर रखी है। पता नहीं यहां इतनी पुलिस फोर्स क्यों लगा रखी है? यहां कोई जंग तो होने नहीं जा रही, नमाज ही हो रही है। हम लोग बहुत सुकून से रहते हैं।

डसॉल्ट एविएशन भारत में बनाएगी फाल्कन-2000 बिजनेस जेट

नई दिल्ली/एजेंसी फ्रांसीसी कंपनी डसॉल्ट एविएशन अब वैश्विक बाजार के लिए भारत में फाल्कन-2000 बिजनेस जेट बनाएगी। इसके लिए पेरिस एयर शो में कंपनी ने रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड की सहायक कंपनी रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर लिमिटेड (आरएएल) के साथ एक समझौता किया है। इस समझौते के बाद भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा और ब्राजील के बाद अगली पीढ़ी के बिजनेस जेट बनाने वाले देशों के कुलीन क्लब में शामिल हो गया है। यह पहली बार है कि जब डसॉल्ट एविएशन फ्रांस के बाहर फाल्कन-2000 जेट का निर्माण करेगा, जिससे भारत रणनीतिक वैश्विक विमानन केंद्र के रूप में स्थापित होगा। बिजनेस एजेंसीयूटिव जेट्स के लिए पहली असेंबली लाइन डसॉल्ट रिलायंस एयरोस्पेस लिमिटेड (डीआरएएल) महाराष्ट्र के नागपुर में स्थापित की जाएगी। यहां जेट का पूर्ण ढांचा और विंग असेंबली संचालन के हस्तांतरण के साथ-साथ प्रमुख सुविधा उन्नयन होगा। जहां से 2028 तक फाल्कन 2000 की पहली उड़ान का मार्ग प्रशस्त होगा। डसॉल्ट एविएशन के अध्यक्ष और सीईओ एरिक ट्रेपियर ने कहा कि यह नया समझौता भारत की 'भेक इन



इंडिया' प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और वैश्विक एयरोस्पेस आपूर्ति शृंखला में भारत को एक प्रमुख भागीदार के रूप में मान्यता दिलाएगा। यह साझेदारी भारत की एयरोस्पेस विनिर्माण क्षमताओं को आगे बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण कदम है, जबकि रणनीतिक रूप से वैश्विक विमानन आपूर्ति शृंखला में एकीकृत है। डसॉल्ट एविएशन फाल्कन 8 और फाल्कन 6 के फ्रंट सेक्शन की असेंबली के अलावा फाल्कन-2000 के पंखों और पूरे धड़ की असेंबली भी डीआरएएल को सौंपेगा। रिलायंस समूह के संस्थापक अध्यक्ष अनिल डी. अंबानी ने कहा? कि यह समझौता

'आत्मनिर्भर भारत' और 'विश्व के लिए भारत में निर्माण' के दृष्टिकोण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत में फाल्कन बिजनेस जेट के निर्माण के लिए डसॉल्ट एविएशन के साथ हमारी साझेदारी देश, विमानन उद्योग और रिलायंस समूह के लिए एक निर्णायक क्षण है। इससे भारत को वैश्विक एयरोस्पेस मूल्य शृंखला में एक प्रमुख शक्ति के रूप में स्थापित करने में मदद मिलेगी।? इस ऐतिहासिक पहल से भारत हाई-एंड बिजनेस जेट निर्माण के लिए एक रणनीतिक केंद्र के रूप में उभरेगा। नई फाइनेल असेंबली लाइन भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बढ़ती मांग

को पूरा करेगी। डसॉल्ट एविएशन और रिलायंस एयरोस्ट्रक्चर के बीच संयुक्त उद्यम? डीआरएएल की स्थापना 2017 में हुई थी। उसी ?के बाद नागपुर के मिहान में एक अत्याधुनिक विनिर्माण सुविधा की स्थापना के साथ परिचालन शुरू हुआ। 2019 में अपना पहला फाल्कन 2-2000 फ्रंट सेक्शन देने के बाद से डीआरएएल ने फाल्कन 2-2000 के लिए 100 से अधिक प्रमुख उप-खंडों को इकट्ठा किया है।? डीआरएएल? को अपने विस्तारित परिचालन का समर्थन करने के लिए अगले दशक में कई सौ इंजीनियरों और तकनीशियनों की भर्ती करने की उम्मीद है।